घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 268- बुधवार 29- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

फेसबुक से डिलीट हुआ पीएम मोदी का वीडियो,मेटा ने मांगी माफी

नई दिल्ली,28 जुलाई 2026। पीएम मोदी के वीडियो को फेसबुक से कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि, मेटा ने इस घटना पर माफी मांग ली है और कंपनी के प्रवक्ता ने वीडियो हटने की वजह तकनीकी गड़बड़ी को बताया है। सूत्रों के अनुसार,केंद्र सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा और इंस्टाग्राम के ग्लोबल हेड को समन किया है। सरकार इस बात की जांच करना चाहती है कि आखिर किस वजह से प्रधानमंत्री के आधिकारिक वीडियो तक लोगों की पहुंच अचानक रोक दी गई। सरकार का मानना है कि इस तरह की घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। यह मामला 28 जुलाई की तड़के सामने आया, जब मेटा के स्वामित्व वाले फेसबुक पर भारतीय यूजर्स कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो नहीं देख पाए। वीडियो खोलने की कोशिश करने पर यूजर्स को एक स्वचालित संदेश दिखाई दिया,जिसमें लिखा था कि कानूनी अनुरोध के कारण भारत में इस वीडियो की पहुंच सीमित कर दी गई है। इससे सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि,बाद में मेटा ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा कि यह किसी कानूनी कार्रवाई का परिणाम नहीं था,बल्कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ। कंपनी ने माफी मांगते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया। भौगोलिक संदर्भ गौरतलब है कि यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेल्फी फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया संदेश था, जिसमें उन्होंने पेपर लीक विवाद और इस मुद्दे पर होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की आगामी कार्रवाई को लेकर खासतौर पर देश के जेन-जी युवाओं को संबोधित किया था।

जापान में फिर कांपी धरती : 7.1 के शक्तिशाली झटके,सुनामी अलर्ट से मचा हड़कंप...

नई दिल्ली,28 जुलाई 2026। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। कुमामोटो क्षेत्र में आए भूकंप की शुरुआती तीव्रता 7.1 मापी गई, जबकि बाद के आकलन में 6.8 की तीव्रता भी सामने आई। करीब 10 किलोमीटर गहराई में आए झटकों के बाद कई इलाकों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, सड़कें टूट गईं और आग लगने की घटनाएं सामने आईं। कम से कम 50 लोगों के घायल होने की सूचना है। भूकंप के बाद जापान के तटीय इलाकों में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। बाद में इसे हटा लिया गया। प्रशासन ने लोगों से समुद्र तट से दूर रहने और संभावित आफ्टरशॉक को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। तेज झटकों से कई स्थानों पर सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हुए। कुछ इमारतों के ढहने और आग लगने की भी सूचना है। कुमामोटो कैसल समेत कई ऐतिहासिक और सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के कारण रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं और कुमामोटो एयरपोर्ट का संचालन बाधित हुआ। भूकंप के बाद क्यूशू के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 40 हजार घरों की बिजली गुल हुई। बिजली बहाली और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने का काम जारी है। जापानी अधिकारियों ने चेताया है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में और झटके महसूस किए जा सकते हैं। प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है और प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल परमाणु संयंत्रों में किसी तरह की असामान्य स्थिति की सूचना नहीं है।

पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी छात्रा की मौत,वीसी कार्यालय के बाहर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

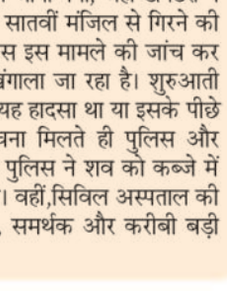

चंडीगढ़,28 जुलाई 2026। पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की पीएचडी छात्रा ज्योति की करंट लगने से मौत हो गई। ज्योति हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली थीं। हादसे के बाद पूरे कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह घटना गर्ल्स हॉस्टल नंबर-10 के पास, हॉस्टल नंबर-8 और यूआईईटी को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते पर हुई। करंट लगने के बाद छात्रा को तुरंत जीएमसीएच-16 अस्पताल ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल करंट लगने की असली वजह की जांच की जा रही है। घटना से नाराज छात्रों ने पहले विद्युत शाखा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में बड़ी संख्या में छात्र कुलपति (वीसी) कार्यालय पहुंच गए और मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्र 'वी वांट जस्टिस' के नारे लगाते रहे और कुलपति के इस्तीफे की मांग की। छात्रों का कहना है कि पिछले साल भी करंट लगने से एक छात्र की मौत हुई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, बिजली व्यवस्था की जांच और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब कुलपति प्रो. रेणु विज का बुधवार को कार्यकाल समाप्त होने वाला है।

7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत,जांच में जुटी पुलिस...

लखनऊ,28 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। लालबाग स्थित नए विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरने के बाद पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व मंत्री के सातवीं मंजिल से गिरने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और घटना के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो सका है कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं,सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पूर्व मंत्री के परिजन, समर्थक और करीबी बड़ी संख्या में जुट गए।

लोक परीक्षाओं में नकल पर शिकंजा और कसेगा,संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश....

राहुल बोले...रेपिस्ट की पैरवी करने वाले को शिक्षा मंत्री बनाया

नई दिल्ली,28 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वर्ष 2024 में लागू कानून को और अधिक प्रभावी एवं कठोर बनाना है, ताकि विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। डॉ. सिंह ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं की घटनाएं किसी एक राज्य या सरकार तक सीमित नहीं रही हैं। उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड,अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा,एम्स,तमिलनाडु लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा तथा पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा सहित कई मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हीं अनुभवों के आधार पर वर्ष 2024 में व्यापक कानून बनाया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। लोकसभा में प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने पर भी हंगामा हुआ। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने रेपिस्ट की पैरवी करने वाले शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया है।

यही बात प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा में कही,हालांकि उनकी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। सदन में प्रियंका की टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। रिजिजू,निशिकांत दुबे और जोशी ने विरोध किया और कहा कि प्रियंका ने जोशी का चरित्र हनन किया। प्रियंका इस बात का सबूत दें और माफी मांगे। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं, जुमले देती है। अखिलेश यादव ने कहा- मजाक मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी,कितनी बड़ी पार्टी बन गई। मजाक में शुरू हुई पार्टी कितनी गंभीर हो गई। इससे सरकार लोकतांत्रिक हो गई।

राहुल बोले...रेपिस्ट का बचाव करने वाले शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया...

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा...देश के शिक्षा मंत्री के तौर पर बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो बलात्कारियों का बचाव करता है। जो व्यक्ति यह कहे कि बलात्कारियों को सुरक्षा की जरूरत है। यह बहुत ही खराब बात है। आज देश के शिक्षा मंत्री वही हैं। पीएम का यह रवैया अजीब है,उनकी कैबिनेट में इतने सारे लोग हैं,वे उनमें से किसी को भी चुन सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कारियों को बचाता है। वाकई हैरान करने वाली बात है।

प्रियंका ने पूछा...सरकार बताए पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया...

बच्चों पर लाठीचार्ज किसके आदेश पर हुआ,इसका जवाब पूरा देश चाहता है। जनता ने सांसदों को अपनी सेवा और जवाबदेही के लिए चुना है। छात्रों की मांग थी कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई हो,शिक्षा माफिया हटे,मंत्री इस्तीफा दें और लाठीचार्ज के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कर माफी मांगी जाए। शिक्षा व्यवस्था की खामियों और पढ़ाई के दबाव से कई छात्र आत्महत्या या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई कराते हैं,फिर भी नौकरी की गारंटी नहीं है।

अखिलेश ने कहा- जो चढ़वा नहीं बचा सके, वे पेपर लीक कैसे बचाएंगे

अखिलेश यादव ने कहा...'पहला आंदोलन देखा, जिसमें बच्चों के मां-बाप ने कहा कि जाओ, आंदोलन करो। अगर यह गलत बात है,तो गृह मंत्री को लाइए, वे सब साफ कर देते हैं। जो लोग चढ़ावा नहीं बचा सके,वो लोग पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। भगवान के दरबार से दान गायब हो गया। उन्होंने कहा...लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 20 परीक्षाएं लीक हो गईं। कोर्ट जाना पड़ा, इसके बाद परीक्षाएं रद्द हुईं।

मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन तेज

मूंग खरीदी समेत 8 सूत्रीय मांगों पर अड़े

मध्यप्रदेश,28 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश में मूंग की पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने और अन्य 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन मंगलवार को और उग्र हो गया है।

नर्मदापुरम से भोपाल के लिए निकले सैकड़ों किसानों का पैदल काफिला पुलिस की सख्त घेराबंदी और बैरिकेडिंग को दरकिनार करते हुए राजधानी की ओर बढ़ रहा है। इस प्रदर्शन के चलते ओबैदुल्लागंज-भोपाल मार्ग और जबलपुर-सुल्तानपुर मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सोमवार सुबह 9 बजे नर्मदापुरम से शुरू हुई इस पदयात्रा को रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक पुख्ता इंतजाम किए थे। नर्मदा पुल, इंदिरा चौक और डोंगरवाड़ा समेत पांच प्रमुख स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेड्स लगाए गए थे। हालांकि, आक्रोशित किसानों ने प्रशासनिक दांव-पेचों को मात देकर सभी रुकावटें हटा दीं। दिनभर चली तीखी बहस और धक्का-मुक्की के बाद किसानों का दल रात को बरखेड़ा पहुँचा और मंगलवार सुबह पुनः मुख्यमंत्री निवास घेराव के उद्देश्य से भोपाल की तरफ रवाना हो गया।आंदोलनकारी किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि औबेदुल्लागंज स्थित गुरुद्वारे में उनके रुकने की पूर्व व्यवस्था थी, जिसे स्थानीय प्रशासन ने जबरन बंद करवा दिया।

इसके चलते कई बुजुर्ग और युवा किसानों को खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी। दूसरी ओर, संभागीय और पुलिस प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और राजमार्गों पर भारी जाम की स्थिति को टालने के लिए यह प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं।

बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार थमा...राजग ने दिखाई एकजुटता,नीरज कुमार की जीत का किया दावा

पटना,28 जुलाई 2026। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन द्वारा खाली की गई पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब 30 जुलाई को मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी प्रमुख घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन किया और राजग प्रत्याशी नीरज कुमार की भारी मतों से जीत का दावा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र की जनता से मिले व्यापक समर्थन से यह स्पष्ट हो गया है कि बांकीपुर की जनता विकास और सुशासन के मुद्दे पर राजग के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आयोजित रोड शो,जनसंपर्क अभियान और विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में मतदाताओं का उत्साह इस बात का संकेत है कि नीरज कुमार बड़े मतांतर से विजयी होंगे। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं बांकीपुर के मतदाताओं से बिहार में विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए राजग प्रत्याशी नीरज कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की है।

सेकंड हैंड कार खरीदने वाले अगर 6 महीने में आरसी ट्रांसफर नहीं कराते तो डीलर के नाम हो जाएगी गाड़ी,सरकार ला रही नया नियम

नई दिल्ली,28 जुलाई 2026। पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री में होने वाली रजिस्ट्रेशन संबंधी परेशानियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अगर कोई खरीदार वाहन खरीदने के 6 महीने यानी 180 दिनों के भीतर अपने नाम पर आरसी ट्रांसफर नहीं कराता है, तो वाहन का मालिकाना हक दोबारा उस डीलर के नाम दर्ज किया जा सकता है, जिससे वाहन खरीदा गया था। मौजूदा व्यवस्था में कई लोग सेकेंड हैंड कार या बाइक खरीदने के बाद लंबे समय तक आरसी ट्रांसफर नहीं कराते हैं। इससे वाहन के पुराने मालिक, खरीदार और डीलर के बीच कानूनी विवाद की स्थिति बन जाती है। नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद वाहन खरीदने वालों को तय समय सीमा के अंदर सभी दस्तावेज पूरे कराकर आरसी अपने नाम करानी होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से आरटीओ रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होंगे और वाहन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। नए नियम के तहत आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कराने में डीलरों की भूमिका भी अहम होगी। यदि 6 महीने के भीतर वाहन का नामांतरण नहीं होता है तो डीलर को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इससे डीलरों पर दबाव रहेगा कि वे खरीदारों से समय पर सभी जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करवाएं।

दतिया विधानसभा उपचुनाव : 30 जुलाई को मतदान,2.20 लाख मतदाता करेंगे 21 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

भोपाल,28 जुलाई 2026। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहां 30 जुलाई को मतदान होगा, जिसमें 2 लाख 20 हजार 344 मतदाता 21 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। ईवीएम में उम्मीदवारों के साथ नोटा का विकल्प भी रहेगा। तीन अगस्त को मतगणना होगी और इसी दिन नतीजे आएंगे। समयऔर कैलेंडर दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार-प्रसार का आज मंगलवार को अंतिम दिन है। शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार और उनके स्थानीय कार्यकर्ता ही घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने समर्थकों और मतदाताओं के बीच आखिरी बार अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,20,344 मतदाता हैं। इनमें 1,16,088 पुरुष और 1,04,246 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 10 अन्य मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में 1,372 दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक उम्र के 1,237 और 443 सर्विस वोटर भी हैं। यही मतदाता 30 जुलाई को ईवीएम में बटन दबाकर 21 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। भाजपा ने चुनाव प्रचार में दतिया के विकास को मुख्य मुद्दा बनाया। पार्टी ने ढाई साल से क्षेत्र में विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरा। भाजपा नेताओं ने मतदाताओं से कहा कि पार्टी प्रत्याशी के जीतने पर रुके हुए विकास कार्यों को पूरा कराया जाएगा। प्रचार के दौरान सरकार के काम और दतिया के विकास को लेकर भी जनता के बीच नेता पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में दतिया उपचुनाव में भाजपा के दावेदार माने जा रहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को निशाने पर रखा। पार्टी ने उनके कार्यकाल के दौरान दतिया में कानून-व्यवस्था और कथित गुंडागर्दी को लेकर लगातार सवाल उठाए।

कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने को भी चुनावी मुद्दा बनाया और इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा। दतिया उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 40-40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार प्रचार में सक्रिय रहे।

सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बनी सहमति

कॉकरोच जनता पार्टी बोली...सभी प्रदर्शनकारियों की एफआईआर वापस होंगी

नई दिल्ली,28 जुलाई 2026। नीट-यूजी गड़बड़ियों और छात्र आंदोलन को लेकर सख्त तेवर अपना रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अल्टीमेटम के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह हरकत में आ गई है। देर रात सरकार के प्रतिनिधियों और सीजेपी नेताओं के बीच हुई एक बेहद अहम और लंबी बैठक में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देने पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। पार्टी ने दावा किया है कि इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद सरकार ने साफ भरोसा दिया है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने बिहार और असम के साथ-साथ अब अन्य सभी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में भी दर्ज मामलों को तुरंत वापस लेने और हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की पक्की गारंटी दी है।

अल्टीमेटम के बाद आधी रात को 3 घंटे चली मैराथन बैठक : गौरतलब है कि दिन में सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिर से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की सीधी चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद सरकार के प्रतिनिधि रात में ही सीजेपी नेताओं से मिलने पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि यह महत्वपूर्ण बैठक करीब दो से तीन घंटे तक चली, जिसमें छात्रों और युवाओं की कानूनी सुरक्षा पर गहन मंथन हुआ। दास ने बताया कि सरकारी प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान ही बिहार और असम गृह विभाग की आधिकारिक अधिसूचनाओं की प्रतियां साझा कीं, जिनमें साफ लिखा है कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जा रही हैं, भविष्य में उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाएगा।

राजस्थान को लेकर भी मिली राहत लिखित गारंटी पर बनी बात

बिहार और असम के बाद अब राजस्थान को लेकर भी आंदोलनकारियों को एक बड़ा और राहत भरा आश्वासन मिला है। प्रवक्ता सौरव दास ने खुलासा किया कि बैठक में सरकार की ओर से स्पष्ट भरोसा दिया गया है कि राजस्थान में भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी प्राधिकरण कार्रवाई नहीं करेगा और वहां न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही आगे की जाएगी। सीजेपी नेताओं ने सरकार के सामने यह गंभीर चिंता जताई थी कि मौखिक आश्वासनों को बाद में जमीन पर लागू नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें ठोस लिखित गारंटी चाहिए। इसके जवाब में सरकारी प्रतिनिधियों ने बिहार गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार और अन्य सभी भाजपा व एनडीए शासित राज्यों की ओर से भी तय भाषा में जल्द ही आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी कर दी जाएंगी, ताकि किसी भी युवा को कानूनी झमेलों का सामना न करना पड़े।

सुप्रीम कोर्ट सख्त...छात्र आंदोलन में पुलिस कार्रवाई की होगी स्वतंत्र जांच

नई दिल्ली,28 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान संसद मार्च में पुलिस कार्रवाई से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं ने बताया कि यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, नागपुर और बिहार में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक बैटन,नाबालिगों की हिरासत और पुलिस की सिविल ड्रेस में हिंसा जैसे कई गंभीर आरोपों पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि इन सभी मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फिलहाल एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही केंद्र समेत सात राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि यह पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा मामला है और सिर्फ दिल्ली की घटना नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सभी याचिकाओं में कुछ समान आरोप देखने को मिले हैं। इनमें एक 19 साल के लड़के की आंखों की रोशनी पैलेट गन के इस्तेमाल से जाने का मामला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल की शिकायत भी है। एक युवती को गंभीर चोट लगने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया। वकीलों पर हमले की भी घटना सामने आई है और एक मीडियाकर्मी पर बेरहमी से हमला किया गया।

संपादकीय

जर्जर सड़कें : विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई

छत्तीसगढ़ में मानसून के साथ एक बार फिर सड़कों की बदहाली बड़ा जनमुद्दा बनकर सामने आ रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर सरगुजा, बस्तर,बिलासपुर,कोरबा और अन्य जिलों तक खराब सड़कें लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई हैं। कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं तो कहीं अधूरे निर्माण कार्य लोगों के लिए रोज़ाना खतरा बन रहे हैं। आम नागरिक, किसान,व्यापारी, विद्यार्थी और मरीज–हर वर्ग इस समस्या से प्रभावित है। सवाल यह है कि जब हर वर्ष सड़क निर्माण और मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं,तब भी स्थिति में स्थायी सुधार क्यों नहीं दिखता?

सरगुजा संभाग इसका ताजा उदाहरण है। डिगमा-सरगवां सड़क हो,कई ग्रामीण संपर्क मार्ग हों या शहर की आंतरिक सड़कें–लंबे समय से लोग इनके निर्माण और मरम्मत की मांग कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई जगह लोगों को आंदोलन, धरना और चक्का जाम का सहारा लेना पड़ रहा है। लोकतंत्र में जनता का विरोध करना उसका अधिकार है, लेकिन यदि बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़े तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

सबसे गंभीर पहलू सड़क सुरक्षा का है। जर्जर सड़कें केवल असुविधा नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं का बड़ा कारण भी हैं। बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता और दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक हादसों का शिकार होते हैं। एम्बुलेंस की रफ्तार प्रभावित होती है, स्कूल बसों में सफर करने वाले बच्चों की सुरक्षा खतरे में रहती है और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में अतिरिक्त समय और लागत दोनों का सामना करना पड़ता है।

समस्या केवल सड़क खराब होने की नहीं है,बल्कि निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी की भी है। कई बार नई बनी सड़कें कुछ ही महीनों में उखड़ने लगती हैं। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहे हैं? यदि नहीं,तो जिम्मेदार एजेंसियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती? जवाबदेही तय किए बिना गुणवत्तापूर्ण निर्माण की उम्मीद करना कठिन है।

ओवरलोड वाहनों की आवाजाही भी एक बड़ी चुनौती है। कई सड़कें सीमित भार क्षमता के अनुरूप बनाई जाती हैं,लेकिन उन पर निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक वजन वाले ट्रक नियमित रूप से चलते हैं। परिणामस्वरूप सड़कें समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। परिवहन और संबंधित विभागों को इस दिशा में सख्ती दिखानी होगी,अन्यथा हर वर्ष मरम्मत पर खर्च होने वाला सरकारी धन व्यर्थ जाता रहेगा।

राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। नई सड़कें,पुल और हाईवे बनना निश्चित रूप से विकास का संकेत हैं,लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है पहले से मौजूद सड़कों को सुरक्षित और उपयोगी बनाए रखना। विकास का सही अर्थ वही है, जिसका लाभ सीधे आम नागरिक तक पहुंचे।

अब आवश्यकता केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि समयबद्ध और पारदर्शी कार्ययोजना की है। जिन सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब है, उनकी प्राथमिकता तय कर शीघ्र मरम्मत और निर्माण कराया जाए। साथ ही गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच, नियमित मॉनिटरिंग और दोषी ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और संबंधित विभागों को मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना होगा।

किसी भी राज्य की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों या बड़ी परियोजनाओं से नहीं होती,बल्कि उन सड़कों से होती है जिन पर आम नागरिक हर दिन चलता है। यदि सड़कें सुरक्षित,मजबूत और टिकाऊ होंगी,तभी विकास के दावे वास्तव में सार्थक माने जाएंगे।

क्या नया परीक्षा कानून और तकनीकी सुधार बचा पाएंगे युवाओं का भविष्य

दुर्गेश्वर राय,गोरखपुर,उत्तरप्रदेश

देश के लाखों युवाओं के सपनों और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में परीक्षाओं की शुचिता वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत और संवेदनशील विषय बना हुआ है। हाल ही में नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुए पेपर लीक विवाद और उसके बाद भड़के राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलनों ने देश की परीक्षा प्रणाली की खामियों को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया। इन व्यापक विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए दबाव के बीच तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का नया कार्यभार संभाला है। छात्रों के इस आक्रोश ने स्पष्ट कर दिया कि केवल कागजी कानून से काम नहीं चलने वाला हैं। इन कानूनों के कठोरता से क्रियान्वयन और व्यवस्था में आमूलचूल तकनीकी सुधार करना ही होगा। इसी पृष्ठभूमि में, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और छात्रों का खोया हुआ विश्वास बहाल करने के लिए प्रशासनिक और विधायी स्तर पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें हालिया संशोधन विधेयक और एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन प्रमुख है।

इस नई व्यवस्था की आवश्यकता को समझने के लिए इसके मूल कानून, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम,2024 पर दृष्टि डालना आवश्यक है। फरवरी 2024 में पारित इस कानून का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना था। उस कानून में परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से गड़बड़ी करने वालों के लिए तीन से पांच साल की सजा और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था,जबकि संगठित माफिया या संस्थागत संलिप्तता के मामले में पांच से दस साल की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि,वर्तमान में देश भर में हुए आंदोलनों ने यह साबित कर दिया कि ये सजाएं संगठित अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त निवारक नहीं बन सकीं। यही कारण है कि नए संशोधन विधेयक के माध्यम से इन दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि शिक्षा माफियाओं के भीतर कानून का वास्तविक भय पैदा किया जा सके और मुकदमों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।

विधायी सख्ती के साथ-साथ,परीक्षा प्रणाली की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ठोस प्रशासनिक कदम भी उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लीक-प्रूफ और तकनीक-संचालित बनाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण समिति का नेतृत्व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष व इन्फोसिस के सह-संस्थापक और प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। यह एक बहु-विषयक समिति है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ,इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे अनुभवी दिग्गज शामिल हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य जोर विशेष रूप से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा प्रणाली को तकनीकी दृष्टिकोण से सुधारने और पुनर्गठित करने पर होगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि हमारी परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी हो,तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए। हालांकि,राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे केवल प्रधानमंत्री की छवि सुधारने का एक प्रयास करार दिया है।

अब यह यक्ष प्रश्न उठता है कि क्या ये नए कदम और विधेयक वास्तव में सुचिता पूर्ण परीक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा करोड़ों युवाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक उत्थान का एकमात्र साधन है,वहां ऐसे सख्त कानूनों और तकनीकी सुधारों का महत्व अत्यधिक है। एक त्रुटिहीन परीक्षा प्रणाली न केवल योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा करती है,बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी सही प्रतिभाओं का योगदान सुनिश्चित करती है। नंदन नीलेकणी जैसे विशेषज्ञ के नेतृत्व में तकनीक का एकीकरण और नए विधेयक के सख्त दंडात्मक प्रावधान मिलकर एक ऐसा मजबूत तंत्र विकसित कर सकते हैं, जिसे भेद पाना संगठित माफियाओं के लिए लगभग असंभव हो जाए। इस पूरी कवायद की सफलता पूरी तरह से इसके जमीनी क्रियान्वयन और व्यवस्था में बैठे लोगों की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करेगी। यदि इन सुधारों को इनकी सच्ची भावना के साथ लागू किया गया, तो यह निश्चित रूप से देश के मेहनती युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

वन्यजीव खत्म तो जंगल खत्म और इंसान की सांसे भी खत्म

डॉ.प्रितम भि.गेडाम

पृथ्वी पर मौजूद हर जीव अपनी अलग पहचान और भूमिका के साथ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता हैं। खाद्य श्रृंखला की हर कड़ी आवश्यक है,क्योंकि किसी एक जीव का भी असंतुलन पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकता हैं। आज के समय में मनुष्य को छोड़कर सभी जीव प्रकृति की रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्वच्छ हवा,साफ पानी और पर्याप्त भोजन सभी के जीवन के लिए जरूरी है, और ये तभी मिल सकते है जब पर्यावरण स्वस्थ और संतुलित हो। सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते है,जबकि पक्षी और वन्य प्राणी बीजों का प्रसार करके नए पौधों और वनों के विकास में सहायता करते हैं। जब जंगलों में जीव-जंतु सुरक्षित रहते है, तब वन हरे-भरे बने रहते है, मौसम का चक्र संतुलित रहता है, जलस्त्रोत सुरक्षित होते है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता हैं। इससे प्रदूषण कम होता है,बीमारियों का खतरा घटता है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती हैं। वास्तव में वन्यजीव प्रकृति के सच्चे संरक्षक है,क्योंकि वे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मनुष्य के बिना प्रकृति स्वयं को तेजी से पुनर्जीवित कर सकती है, किंतु प्रकृति के अभाव में मानव जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है,इसलिए प्रकृति और वन्यजीवों का संरक्षण हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं।

सभी जीवों को अपने प्राकृतिक अधिवास में जीने का अधिकार है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन्यजीवों और मानवों के बीच संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया हैं। इसमें हानि दोनों को होती है, मनुष्य भी जान गवांते है और वन्यजीव भी। आजादी के पहले राजा-महाराजाओं और अंग्रेजों ने शिकार करके जंगली जानवरों की संख्या बेहद कम कर दी। अधिकतम प्रजातियां तो हमेशा के लिए विलुप्त भी हो गयी। तेजी से घटती वन्यजीवों की संख्या को बचाने सरकार ने कानून बनाये हैं।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

आयआयटी बॉम्बे और सस्त्रा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक रिसर्च में पाया गया कि साल 2015 - 2019 के बीच,देश में हर 1 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ने के बदले लगभग 18 वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म हो गए। प्राकृतिक घने और पुराने जंगल तेज़ी से खत्म हो रहे है,अगर यही स्थिति रही तो, इसमें रहनेवाले वन्यजीव भी बुरे तरीके से प्रभावित होंगे ही,अर्थात उनका जीवन संकट में होगा। आज देश में बढ़ते शहरीकरण के कारण,पारंपरिक खेती कम हो रही है,शहरों के आसपास के गाँवो में कांक्रीट के जंगल बढ़ रहे है,जिसके कारण जंगल सिकुड़ रहे और मानवीय गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों के पास,प्रकृति की गोद में लोगों को आबाद करने के लिए फार्महाउस बनाने का ट्रेंड चल पड़ा हैं। विकास के नाम पर जंगलों के बीच से महामार्ग बनाएं जा रहे और जंगलों को काटकर उत्खनन का काम चल रहा हैं। इससे सीधे तौर पर वन्यजीवों के प्राकृतिक अधिवास नष्ट हो रहे हैं। साल-दर साल प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं।

जिन वनों में बाघ रहते है, वहां का पारिस्थितिक तंत्र अधिक समृद्ध और संतुलित होता हैं। बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि पूरे जंगल के संरक्षक हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें विशाल,सुरक्षित और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त आवास चाहिए। ऐसे क्षेत्रों की रक्षा से असंख्य वन्य प्राणी, वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव और पूरी जैव-विविधता सुरक्षित रहती हैं। बाघ शाकाहारी जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं, जिससे वनस्पतियों का अत्यधिक दोहन रुकता है और प्राकृतिक संतुलन बना रहता हैं। सुरक्षित जंगल अधिक कार्बन सोखते है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने में मदद करते हैं। साथ ही,ये घने वन वर्षा जल के प्रवाह को नियंत्रित कर बाढ़ की तीव्रता घटाते है और करोड़ों लोगों को मीठा पानी देते हैं। इसलिए बाघों और उनके आवासों की रक्षा पूरे पर्यावरण की रक्षा हैं। यह संरक्षण मानव जीवन, कृषि, जलस्त्रोतों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं।

हर साल 29 जुलाई को अंतराष्ट्रीय बाघ दिवस खतरे में पड़ी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों और उनके प्राकृतिक अधिवास को बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है,बाघ बचाओं,जंगल बचाओं, प्रकृति बचाओं यह नारा दिया जाता है, क्योंकि यह बचेंगें तो ही हम बचेंगें,यह समझना बहुत जरुरी हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम के अनुसार,दुनिया भर के जंगल में सिर्फ़ 5,660 टाइगर बचे हैं। देश के नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट स्टेटस ऑफ़ टाइगर्स इन इंडिया : को-प्रिडेटर्स एंड प्रे 2022 के अनुसार, इनमें से 3,682 भारत में पाए जाते हैं। हर साल सड़क दुर्घटनाओं,खेतों में करंट से,खुले कुएं में गिरकर और शिकार द्वारा असंख्य वन्यजीवों की बेदर्दी से असमय मौत होती हैं। विदर्भ क्षेत्र (महाराष्ट्र) के समाचारपत्रों में अक्सर वन्यजीवों के मौत की खबर सुर्खियां बनी रहती है, विशेषकर बाघों के मौत की। आये दिन बाघों की मौत चिंता का विषय है, पिछले छह माह में महाराष्ट्र में कुल 24 बाघों की मौत हो चुकी हैं। साल 2025 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में कुल 54 बाघों की जान चले गयी और महाराष्ट्र राज्य के वनमंत्री गणेश नाईक ने बताया कि, महाराष्ट्र राज्य में 41 बाघों की मौत हुयी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अनुसार, हर बाघ की पहचान उसकी धारियों के अलग पैटर्न से होती है,ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। मादा बाघ अपने शावकों से संवाद करने के लिए कानों के पीछे बने सफेद निशानों का उपयोग करती है,जो उनके लिए संकेतों की तरह काम करते हैं। दुनिया के आधे से अधिक बाघ भारत में पाए जाते है,जो देश की समृद्ध जैव-विविधता का बड़ा प्रमाण हैं। बाघ अलग-अलग परिस्थितियों में गुर्राने,दहाड़ने,कराहने, फुफकारने और हांफने जैसी आवाज़ों से संवाद करते हैं। माना जाता है कि बाघ लगभग 20 लाख वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन पिछले सौ वर्षों में मानवीय हस्तक्षेप,जंगलों की कटाई और अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में लगभग 97 प्रतिशत की कमी आई हैं। इसी वजह से इन्हें लुप्तप्राय प्रजाति माना गया है,आज भी अवैध शिकार इनके लिए बड़ा खतरा हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एशिया में इनके संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा हैं। वर्ष 2016 में कुछ क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ने की खबर मिली, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया में इनकी आबादी अब भी घट रही हैं।

मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी के पास आज कानूनी अधिकार,उन्नत तकनीक, प्रसार माध्यम,सरकार,न्याय प्रणाली, सोशल मीडिया,रिश्तेदार, मित्र-परिवार और समाज है,फिर भी उच्चशिक्षित और जागरूक मनुष्य होकर भी अनेक मौकों पर वह खुद को ठगा सा महसूस करता हैं। अपनी समस्या को लेकर सरकारी दफ्तरों,नेताओं और न्यायालय के चक्कर काटकर भी बहुधा संतोषजनक समाधान नहीं पाता हैं। बरसात में बाढ़ की समस्या, गर्मी में अकाल, लू और जल की कमी,ठंडी में कोहरे और हाइपोथर्मिया की समस्या और प्राकृतिक आपदाएं। अगर इंसान सर्व सुविधा सम्पन्न होकर ऐसी परिस्थितियों में विवश हो जाता है, तो फिर इसके मुकाबले वन्यपशुओं की स्थिति का तो अंदाजा भी लगाना मुश्किल हैं। फिर सोचिए जरा मूक वन्यजीवों के नजरिये से, जिन्हे मनुष्य से नहीं बल्कि प्रकृति से केवल भूख-प्यास की पूर्ति की आस है और प्रकृति समस्त जीवों के भरणपोषण में बहुत सक्षम है, अगर मानवी हस्तक्षेप न हो तो। फिर हम वन्यजीवों को परेशान कर रहे है क्या? या वन्यजीव हमें परेशान कर रहे है? बढ़ते वन्यजीव व मानवी संघर्ष के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? वक्त रहते इसका गहराई से विचार करना बहुत जरुरी हैं।

महान गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का अवसर

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु:
गुरुर्देवो महेश्वराय।
गुरु: साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्रीगुरवे नम:॥

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

भारतीय संस्कृति में गुरु को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और अज्ञान का नाश करने वाला माना गया है। गुरु केवल अक्षरज्ञान देने वाला शिक्षक नहीं,बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को गढ़ती है, उसके भीतर सोई हुई चेतना को जगाती है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान करती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व इसी महान गुरु-परंपरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। परंतु यह दिन केवल गुरु-वंदना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह वह पावन क्षण है,जब प्रत्येक शिष्य को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने गुरु के उपदेशों, संस्कारों और आदर्शों को अपने जीवन और समाज में श्रेष्ठ कर्मों के रूप में मूर्त रूप देगा।

गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास से है, जिन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा का महान शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया,महाभारत की रचना की, अठारह पुराणों का संकलन किया और भारतीय चिंतन को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। इसलिए उन्हें जगतगुरु की संज्ञा दी जाती है। उनकी स्मृति में मनाया जाने वाला यह पर्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह समाज के कल्याण का माध्यम बने।

भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान माता-पिता के समान ही नहीं,अनेक संदर्भों में उनसे भी ऊँचा माना गया है, क्योंकि माता-पिता जन्म देते हैं,जबकि गुरु जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गुरु गोविन्द

दोऊ खड़े,
काके लागूं पाय।
बलिहारी गुरु आपने,
गोविन्द दियो बताय।

दोहा केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं,बल्कि यह बताता है कि गुरु ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है। यदि जीवन में गुरु का मार्गदर्शन न हो तो ज्ञान अधूरा रह जाता है और प्रतिभा दिशा खो देती है।

आज का समय केवल सूचना का युग नहीं, बल्कि विवेक का भी युग है। इंटरनेट,कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान के असंख्य स्रोत उपलब्ध करा दिए हैं,परंतु सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता आज भी गुरु ही विकसित करता है। सूचना मनुष्य को विद्वान बना सकती है,किंतु गुरु उसे विवेकवान बनाता है। इसलिए गुरु का महत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था–

शिक्षा वह है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े,बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा केवल पाठ्य-पुस्तकों से नहीं आती, बल्कि गुरु के व्यक्तित्व,उनके आचरण और उनके जीवन-दर्शन से प्राप्त होती है। गुरु अपने शिष्य के भीतर छिपी हुई संभावनाओं को पहचानता है और उन्हें समाजोपयोगी दिशा देता है। महात्मा गांधी का विश्वास था कि चरित्रहीन शिक्षा समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह आज पहले से अधिक प्रासंगिक है। यदि शिक्षा केवल रोजगार का साधन बन जाए और जीवन-मूल्यों से हट जाए,तो समाज प्रगति के बावजूद शांति और नैतिकता खो देता है। इसलिए गुरु की भूमिका केवल रोजगार दिलाने तक सीमित नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण तक विस्तृत है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था–

सच्चा शिक्षक वही है जो हमें स्वयं सोचने की प्रेरणा देता है। गुरु का वास्तविक दायित्व है। वह शिष्य को उत्तर नहीं देता,बल्कि सही प्रश्न पूछना सिखाता है। वह अनुकरण नहीं,बल्कि आत्मबोध का मार्ग दिखाता है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का कहना था श्रेष्ठ शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा तीनों का संगम होता है।

डॉ. कलाम स्वयं अपने शिक्षकों का उल्लेख अत्यंत सम्मान के साथ करते थे और स्वीकार करते थे कि उनके व्यक्तित्व की नींव उनके गुरुओं ने ही रखी। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक महान व्यक्तित्व के पीछे किसी न किसी गुरु का अमूल्य योगदान रहा है। भगवान श्रीराम के जीवन को महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने दिशा दी। भगवान श्रीकृष्ण ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर गुरु-दक्षिणा का आदर्श प्रस्तुत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व निर्माण में समर्थ गुरु रामदास और माता जीजाबाई के संस्कार निर्णायक रहे। स्वामी विवेकानंद को विश्व मंच तक पहुँचाने वाले उनके गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को केवल सम्राट नहीं बनाया,बल्कि भारत के इतिहास की दिशा बदल दी।

धुंधलाती गुरु-गरिमा को पुन:स्थापित करने का महापर्व

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

भारतीय संस्कृति का प्राण यदि किसी एक तत्व में समाहित है, तो वह है- गुरु। गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं,बल्कि जीवन को दिशा देने वाली चेतना है। वह मनुष्य के भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाता है,उसके व्यक्तित्व को संस्कारित करता है और उसे आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसीलिए भारतीय मनीषा ने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। प्रसिद्ध वचन-'गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर:'-केवल स्तुति नहीं, बल्कि गुरु की उस महत्ता का उद्घोष है जिसके बिना जीवन का कोई भी आयाम पूर्ण नहीं हो सकता। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं,बल्कि आत्मचिंतन, कृतज्ञता और जीवन-मूल्यों के पुनर्जागरण का अवसर है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, पद या प्रसिद्धि नहीं,बल्कि सही मार्गदर्शन है। जिसने जीवन को सही दिशा दे दी, उसने सब कुछ दे दिया।

भारतीय परंपरा में इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है,इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया,महाभारत की रचना की और भारतीय ज्ञान-परंपरा को सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। उन्होंने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि मानवता को विचारों की ऐसी ज्योति दी जो सहस्राब्दियों से विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा ज्ञान और जीवन-दृष्टि के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। गुरु का अर्थ केवल शिक्षक नहीं है। शिक्षक सूचना देता है, गुरु चेतना जगाता है। शिक्षक बुद्धि को विकसित करता है, गुरु व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। शिक्षक व्यवसाय हो सकता है, लेकिन गुरु सदैव तपस्या होता है। गुरु वह है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को हटाकर आत्मविश्वास, विवेक और करुणा का दीप प्रज्वलित करे। गुरु का स्पर्श केवल मस्तिष्क तक नहीं पहुँचता,वह आत्मा तक उतरता है। मेरे जीवन में गुरु का स्वरूप केवल एक पूज्य व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर प्रकाश-स्तंभ का रहा है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने अपने प्रत्यक्ष सान्निध्य,प्रेरणाओं और जीवन-दृष्टि से मुझे बार-बार यह अनुभव कराया कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, वे जीवन के प्रत्येक अंधकार में दिशा दिखाने वाले दिव्य पथ-प्रदर्शक होते हैं।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा,जेन-जी की ताकत और राजनीति के लिए बड़ा संदेश

योगेश कुमार गोयल
नजफ्फगढ़, नई दिल्ली

भारतीय लोकतंत्र ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जनता की आवाज यदि संगठित,शांतिपूर्ण और निरंतर हो तो वह सबसे शक्तिशाली सत्ता को भी आत्ममंथन के लिए विवश कर सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं है बल्कि यह उस लोकतांत्रिक दबाव की स्वीकारोक्ति भी है,जो पिछले कई सप्ताह से देशभर के लाखों युवाओं ने अपने धैर्य,अनुशासन और दृढ़ता से निर्मित किया। हाल के घटनाक्रमों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा हुई और आंदोलन के नेतृत्व ने दावा किया कि उनकी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली गई। यह घटना केवल शिक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले वर्षों में इसे उस मोड़ के रूप में याद किया जाएगा,जब भारत की जेन-जी ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी से भी संचालित होता है।

इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसकी शुरुआत किसी स्थापित राजनीतिक दल ने नहीं की। यह आंदोलन सोशल मीडिया की दुनिया से निकला,व्यंग्य से शुरू हुआ और देखते ही देखते करोड़ों युवाओं की सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया। जिस 'कॉकरोच' शब्द का प्रयोग कथित रूप से अपमान के लिए किया गया था, उसी शब्द को युवाओं ने अपने आत्मसम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह अपमान को भी प्रतिरोध की शक्ति में बदल देता है। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को एक नया पाठ पढ़ाया है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाले अभियान केवल कुछ दिनों की सनसनी होते हैं लेकिन इस बार 'डिजिटल अभियान' सड़क पर उतरा, शांतिपूर्ण जनआंदोलन में बदला और अंततः सत्ता को निर्णय लेने के लिए बाध्य कर गया। इससे स्पष्ट है कि भारत की नई पीढ़ी केवल 'लाइक' और 'शेयर' तक सीमित नहीं है; वह लोकतांत्रिक भागीदारी की नई भाषा लिख रही है।

हालांकि इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय केवल आंदोलन की सफलता को नहीं बल्कि उसके संयम को भी जाता है। अनेक स्थानों पर तनाव और पुलिस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन के नेतृत्व ने लगातार संवैधानिक और शांतिपूर्ण

विरोध की अपील की। यही कारण है कि इस आंदोलन को व्यापक सामाजिक समर्थन मिला। लोकतंत्र में किसी भी जनआंदोलन की नैतिक शक्ति उसकी अहिंसा और अनुशासन से ही आती है। हालांकि इस जीत के साथ कुछ गंभीर प्रश्न भी खड़े होते हैं। क्या केवल एक मंत्री का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था की उन गहरी समस्याओं का समाधान कर देगा, जिनके कारण यह आंदोलन जन्मा? क्या प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी? क्या भर्ती परीक्षाओं में वर्षों से चली आ रही देरी खत्म हो जाएगी? क्या करोड़ों युवाओं को रोजगार की नई संभावनाएं मिल जाएंगी? इन प्रश्नों का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण उदाहरण अवश्य है किंतु इसे अंतिम समाधान मान लेना भूल होगी। यदि परीक्षा प्रणाली की संरचनात्मक कमियां जस की तस रही, यदि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों में पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा नहीं बढ़ी, यदि दोषियों को समयबद्ध दंड नहीं मिला और यदि भर्ती प्रक्रियाएं पहले की तरह वर्षों तक अटकी रही तो आज का यह जनसंतोष भविष्य में फिर नए रूप में सामने आ सकता है। सरकार के लिए भी यह आत्मचिंतन का अवसर है। लोकतंत्र में किसी आंदोलन को केवल राजनीतिक षड्यंत्र मानकर खारिज कर देना कभी भी दूरदर्शी नीति नहीं हो सकती। शुरुआत में यदि युवाओं की शिकायतों को अधिक गंभीरता से सुना जाता,संवाद स्थापित किया जाता और सुधारों की स्पष्ट समय सीमा घोषित की जाती तो शायद स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। अंततः सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और यही लोकतंत्र की सही दिशा भी है।

विपक्ष के लिए भी यह अवसर आत्ममंथन का है। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि इसकी ऊर्जा किसी पारंपरिक राजनीतिक दल से नहीं बल्कि युवाओं की स्वतःस्फूर्त भागीदारी से आई। इससे स्पष्ट संदेश मिलता है कि आज की पीढ़ी केवल राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहती है। यदि विपक्ष भी केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित रहेगा और शिक्षा सुधार के ठोस एजेंडे पर गंभीरता नहीं दिखाएगा तो वह भी युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा। मीडिया और खासकर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर भी प्रश्न उठते हैं। प्रारंभिक दिनों में आंदोलन को सोशल मीडिया की सनसनी समझने वाले अनेक मंच बाद में उसकी गंभीरता को स्वीकार करने के लिए विवश हुए। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व केवल टकराव के दृश्य दिखाना नहीं बल्कि उन कारणों की पड़ताल करना भी है, जिनके कारण लाखों युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय लोकतंत्र में एक नई राजनीतिक संस्कृति की भी शुरुआत की है। यह संस्कृति व्यक्ति-पूजा से अधिक मुद्दों पर आधारित है। यह आंदोलन किसी जाति,भाषा, क्षेत्र या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समान अवसर,निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेह शासन जैसी सार्वभौमिक लोकतांत्रिक मांगों पर आधारित था। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति रही। आज आवश्यकता इस विजय का उत्सव मनाने से अधिक उसके संदेश को समझने की है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होगा तो भविष्य भी होगा सुरक्षित : आईजी दीपक कुमार झा

होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम,विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को दिए तनाव,नशे और सोशल मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सकारात्मक सोच विकसित करने तथा उन्हें तनाव,नशे और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा,चिकित्सा, पुलिस प्रशासन, समाजसेवा एवं आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए मानसिक रूप से सशक्त बनने,जीवन में अनुशासन अपनाने और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने का संदेश दिया। कार्यक्रम की संयोजक समाजसेवी श्रीमती शिल्पा पाण्डेय थीं। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सरगुजा दीपक कुमार झा,नगर निगम सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा प्रमुख विद्या दीदी, बिशप राइट रेवरेन्ड एन्टनी बड़ा,वरिष्ठ समाजसेवी उमाकांत पाण्डेय,मनोचिकित्सक डॉ. इन्द्रप्रकाश तथा डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार एवं विद्यार्थियों ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ शिक्षक सुनील तिवारी के स्वागत उद्बोधन से हुआ।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल शैक्षणिक उपलब्धियां ही पर्याप्त नहीं हैं,बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ, आत्मविश्वासी और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना भी उतना ही आवश्यक है।

कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती शिल्पा पाण्डेय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज समाज में सामने आने वाली अनेक आपराधिक घटनाओं में किशोरों की संलिप्तता चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल पढ़ाई में ही नहीं,बल्कि संस्कार, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने व्यवहार, विचार और मित्रों के चयन में सजग रहें तथा समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनने का संकल्प लें। समाजसेवी उमाकांत पाण्डेय ने बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की जानकारी दी और उन्हें अनुशासित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। मनोचिकित्सक डॉ. इन्द्रप्रकाश ने मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि परीक्षा का दबाव,पारिवारिक अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कई बार बच्चों में तनाव और अवसाद का कारण बन जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को क्रोध पर नियंत्रण रखने,अपनी भावनाओं को परिवार और शिक्षकों से साझा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह लेने की सीख दी। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य,शिक्षा, परिवार और भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि नशे की लत रिश्तों में दूरी पैदा करती है और व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी कमजोर बना देती है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा प्रमुख विद्या दीदी ने आध्यात्मिक जीवन और सकारात्मक सोच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मन की शांति और आत्मबल ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशामुक्त जीवन अपनाने तथा अपने परिवार और समाज में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया। बिशप राइट रेवरेन्ड एन्टनी बड़ा ने कहा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति सीखते हुए आगे बढ़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मिक शांति, क्षमा, प्रेम और सेवा की भावना को जीवन में अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि यही मूल्य उन्हें सफलता और संतुलित जीवन की ओर ले जाएंगे। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा दीपक कुमार झा ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपराधों पर नियंत्रण केवल कठोर दंड से संभव नहीं है, बल्कि अपराध होने से पहले उसकी रोकथाम अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अच्छी संगति, परिवार के साथ संवाद, अनुशासित जीवन और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक का सदुपयोग करने और अपने चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। नगर निगम सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु और माता-पिता का सम्मान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने शिक्षकों का आदर करने, माता-पिता की आज्ञा का पालन करने और अनुशासित जीवनशैली अपनाने की अपील की। विद्यालय की प्राचार्य डॉ. सि. जेस्सी ने अपने संबोधन में कहा कि यदि इस कार्यशाला से मिली दो अच्छी बातें भी विद्यार्थी अपने घर जाकर अभिभावकों के साथ साझा करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कार्यक्रम का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं,बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय संसद की छात्र उपाध्यक्ष शाम्भवी सिंह ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन शिक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय ने किया। पूरे आयोजन के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

15 साल से जर्जर डिगमा-सरगवां सड़क बनाने की उठी मांग

सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिंद ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को लिखा पत्र,बोले...गड्ढों से हादसों का खतरा,जल्द हो निर्माण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के बाहरी हिस्से में बनारस रोड को प्रतापपुर रोड से जोड़ने वाली डिगमा-सरगवां सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर एक बार फिर सड़क निर्माण की मांग तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं वर्ष 2023 के विधायक प्रत्याशी रहे सुजान बिंद ने उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव को पत्र लिखकर विगत डेढ़ दशक से जर्जर इस मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की है। सुजान बिंद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि डिगमा-सरगवां सड़क अंबिकापुर शहर के किनारे स्थित होने के कारण रिंग रोड (बाईपास) के रूप में उपयोग की जाती है। इस मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी मालवाहक वाहन गुजरते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 टन क्षमता वाली इस सड़क पर 40 से 50 टन तक भार वाले ट्रकों का आवागमन हो रहा है, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का गोदाम,स्कूल और कॉलेज स्थित हैं। इसके कारण विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों का प्रतिदिन इसी मार्ग से आवागमन होता है। सड़क की खराब स्थिति के चलते कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने 24 जुलाई को चक्का जाम कर अपना विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। सुजान बिंद ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव से डिगमा-सरगवां सड़क का शीघ्र निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा है कि इससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में लंबे समय से बनी समस्या का समाधान हो सकेगा।

'डीईओ से शिकायत : जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद हॉली क्रॉस और मोंट फोर्ट में अब भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें, अभिभावक संघ ने उठाए गंभीर सवाल

जिला अभिभावकगण संघ का आरोप...चुनिंदा अभिभावकों से सहमति लेकर थोपा गया फैसला,महंगी किताबों से बढ़ रहा आर्थिक बोझ, जिला शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई की मांग...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से संचालित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद शहर के दो प्रमुख निजी विद्यालयों–हॉली क्रॉस स्कूल और मोंट फोर्ट स्कूल–पर इन निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में जिला अभिभावकगण संघ,सरगुजा ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। संघ के अध्यक्ष नीलेश सिंह ने शिकायत में कहा है कि जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दोनों विद्यालयों में महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। आरोप है कि इससे न केवल प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना हो रही है, बल्कि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी डाला जा रहा है।

चुनिंदा अभिभावकों की बैठक कर लिया गया फैसला

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विद्यालय प्रबंधन ने हाल ही में केवल कुछ चुनिंदा और करीबी अभिभावकों की बैठक बुलाकर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें जारी रखने के पक्ष में सहमति दर्शा दी। संघ का कहना है कि अधिकांश अभिभावकों से कोई राय नहीं ली गई,फिर भी इसे सभी की सहमति बताकर निर्णय लागू कर दिया गया।

आर्थिक शोषण और आदेशों की अनदेखी का आरोप

जिला अभिभावकगण संघ का कहना है कि प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें और अन्य शिक्षण सामग्री एनसीईआरटी की तुलना में काफी महंगी होती हैं। इससे हर वर्ष अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है। संघ ने इसे शिक्षा के व्यावसायीकरण का उदाहरण बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।

डीईओ से ये मांगी गई कार्रवाई

संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि दोनों विद्यालयों में तत्काल जांच कराई जाए,जिला प्रशासन के निर्देशों के विपरीत संचालित की जा रही प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकों पर रोक लगाई जाए तथा यदि आदेशों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

शहर की बदहाल व्यवस्था पर युवा कांग्रेस का हमला,निगम को सौंपा मांगपत्र...

सड़क,पानी,सफाई,स्ट्रीट लाइट व कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाया,जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर में जर्जर सड़कों, पेयजल संकट, बिगड़ी सफाई व्यवस्था, बंद स्ट्रीट लाइट और निगम कर्मचारियों के लंबित वेतन जैसे मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस ने मंगलवार को नगर निगम प्रशासन को घेरा। संगठन ने इन समस्याओं को आम जनता की रोजमर्रा की परेशानी बताते हुए नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली के रूप में नगर निगम कार्यालय पहुंचे। पुलिस की बैरिकेडिंग के बीच कार्यकर्ता निगम के मुख्य द्वार तक पहुंच गए, जहां कुछ देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी की स्थिति बनी। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त डीएन कश्यप को मांगपत्र सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम के 48 वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। बारिश के कारण अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित है और रिंग रोड सहित कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। प्रमुख चौक-चौराहों के सीसीटीवी कैमरे बंद रहने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा प्लेसमेंट कर्मचारियों का सात से आठ माह से लंबित वेतन तत्काल जारी करने की मांग की गई। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम ने शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की तो चरणबद्ध आंदोलन तेज किया जाएगा। इधर, नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने बताया कि ज्ञापन में शामिल मांगों पर चर्चा के लिए युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुधवार को बुलाया गया है।

जिन समस्याओं का तत्काल निराकरण संभव होगा,उन पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में नियमित सफाई कराई जा रही है तथा बारिश के दौरान जलापूर्ति प्रभावित होने और पानी कुछ समय के लिए मटमैला होने की स्थिति बन सकती है,लेकिन नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

रेलवे स्टेशन पर लावारिस ट्रॉली बैग में मिली 33.66 लीटर अंग्रेजी शराब,तस्कर फरार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

रेलवे स्टेशन परिसर में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक लावारिस ट्रॉली बैग से 33.66 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध युवक आरपीएफ जवानों को देखकर बैग छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब्त शराब की कीमत लगभग 25,470 रुपए आंकी गई है। मामले में गांधीनगर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 26 जुलाई की सुबह करीब 8.55 बजे अंबिकापुर रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ की नियमित चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान पार्किंग स्टाफ ने प्रधान आरक्षक एवं उपनिरीक्षक जी. खुंटिया को सूचना दी कि एक युवक चॉकलेटी रंग का ट्रॉली बैग लेकर घूम रहा है, जो काफी भारी प्रतीत हो रहा है। सूचना पर आरपीएफ जवानों ने युवक को रोककर पोस्ट में आने के लिए आवाज लगाई। खुद को घिरता देख वह ट्रॉली बैग छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद आरपीएफ ने गवाहों की मौजूदगी में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ट्रॉली बैग की तलाशी ली। बैग के अंदर से हनी बी ब्रांड की 129 और ओल्ड मोंक ब्रांड की 58, कुल 187 शीशियां (प्रत्येक 180 एमएल) अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कुल शराब की मात्रा 33 लीटर 660 मिलीलीटर तथा अनुमानित कीमत 25,470 रुपए है। आरपीएफ ने मौके पर जब्ती पंचनामा तैयार कर शराब को जब्त किया और वैधानिक कार्रवाई के लिए गांधीनगर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया।

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

सेवा किटी ने लिए सामाजिक सरोकारों से जुड़े अहम फैसले

मूकबधिर विद्यालय में पठन सामग्री वितरण,स्वतंत्रता दिवस पर निबंध प्रतियोगिता व रुचि केंद्र शुरू करने का निर्णय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सेवा किटी की मासिक बैठक में सामाजिक एवं रचनात्मक गतिविधियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मूकबधिर विद्यालय के बच्चों को पठन-पाठन सामग्री वितरित करने,शीघ्र ही 'रुचि केंद्र' का शुभारंभ करने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विगत वर्षों की तरह निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में संस्था की गतिविधियों को नियमित बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक दो माह में सदस्यों की बैठक आयोजित करने पर भी सहमति बनी। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हुए आयोजन की जिम्मेदारी दीपमाला सिंह, सुनीता दास,अंजना परिहार, हिना परवीन,स्मिता तिवारी एवं बोनी डे को सौंपी गई। बैठक की अध्यक्षता संयोजिका वंदना दत्ता ने की। इस दौरान वरिष्ठ सदस्य संतोष पांडे,मधु चौधरी, लिली बसु,गायत्री अग्रवाल,मिलन शर्मा, आतिशी भट्टाचार्य,सुधा तिवारी, नमिता चावला,सत्या दुबे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहीं। सभी ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

महामाया पहाड़ पर मिले कंकाल ने खोला गुमशुदगी का राज,पहचान के बाद हत्या की आशंका गहराई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

महामाया पहाड़ पर सड़ी-गली अवस्था में मिले कंकाल की गुत्थी दो दिन बाद सुलझ गई,जब उसकी पहचान शहर के मायापुर निवासी शुभम कश्यप (37) के रूप में हुई। पहचान होते ही मामला नया मोड़ ले गया है। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफन शव को कब्र से निकलवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। 25 जुलाई को वन कर्मचारियों ने महामाया पहाड़ के सुनसान इलाके में पेड़ से फंदे पर लटकता मानव कंकाल देखा था। लगातार बारिश के कारण शव का अधिकांश हिस्सा गलकर नीचे गिर चुका था,जबकि सिर का हिस्सा फंदे से लटका हुआ था। सूचना पर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया। घटनास्थल से चप्पल, कपड़े और कुछ दवाइयां बरामद कर पुलिस ने शिनाख्त शुरू की। पहचान नहीं होने पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को वहीं दफना दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने गुमशुदगी के मामलों का मिलान किया तो पता चला कि मायापुर निवासी शुभम कश्यप 11 जुलाई से लापता था। परिजनों ने 13 जुलाई को कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बरामद कपड़ों और कंधे पर बने टैटू के आधार पर परिजनों से पहचान कराई, जिसके बाद शव की पहचान शुभम के रूप में हुई। पहचान की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए कब्र से शव निकलवाया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। इधर,परिजनों ने पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल से मिले वीडियो और मौके का निरीक्षण करने के बाद उन्हें आत्महत्या की संभावना नहीं लगती। उनका आरोप है कि शुभम की हत्या कर उसके गले में तार लपेटा गया और बाद में साक्ष्य छिपाने के लिए शव को पेड़ पर लटका दिया गया। उनका यह भी कहना है कि शुभम नशे का आदी जरूर था,लेकिन वह आत्महत्या के लिए इतनी सुनसान जगह पर नहीं जाता,जहां सामान्यतः किसी का आना-जाना नहीं होता। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या,दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है।

संभाग स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता: होली क्रॉस सर्वश्रेष्ठ,सैनिक स्कूल उपविजेता

दोनों विद्यालयों को 'बेस्ट स्कूल इन चेस' सम्मान, जल्द होगी अंतर-विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

संभाग स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल, अंबिकापुर को 'बेस्ट स्कूल इन चेस (विजेता)' तथा सैनिक स्कूल, अंबिकापुर को 'बेस्ट स्कूल इन चेस (रनर-अप)' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शतरंज संघ के पदाधिकारियों ने दोनों विद्यालयों को स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। सैनिक स्कूल में यह सम्मान उप-प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पी. श्रीनिवास ने प्राप्त किया, जबकि होली क्रॉस कॉन्वेंट की ओर से प्राचार्या जेस्सी टेक्केन ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर सैनिक स्कूल की ओर से प्रकाश तिवारी, प्रदीप डांगरे एवं महेश सिन्हा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल पी. श्रीनिवास ने शतरंज के प्रति विशेष रुचि व्यक्त करते हुए विद्यालयों में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। शतरंज संघ सरगुजा ने बताया कि जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के प्रदेश महासचिव वीके राठी तथा सीआईएस हेड अब्दुल शमीम के मार्गदर्शन में होली क्रॉस कॉन्वेंट,सैनिक स्कूल,ओपीएस, कार्मेल और मॉन्टफोर्ट स्कूल के बीच उच्च स्तरीय अंतर-विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराना और विद्यालयों में शतरंज को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय निर्णायक अनिश अंसारी, राष्ट्रीय निर्णायक प्रदीप मंडल, शतरंज संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा,उपाध्यक्ष एसएसपी वर्मा, संभाग संयोजक बी. मणियन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन आदेश का शिक्षकों ने किया विरोध

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का जुलाई माह का वेतन ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर आहरित करने के लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन,सरगुजा ने आदेश को अव्यावहारिक बताते हुए इसे तत्काल संशोधित करने की मांग की है। फेडरेशन के जिलाध्यक्ष संदीप कुमार पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश के अनेक विद्यालय दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति के लिए उपयोग किए जा रहे वीएसके ऐप में भी कई तकनीकी खामियां हैं। कई बार शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहते हैं, लेकिन ऐप गलत लोकेशन दिखाता है, विद्यालय से दूरी अधिक बताता है या सर्वर ठीक से काम नहीं करता। ऐसे में शिक्षक चाहकर भी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते। उन्होंने बताया कि इन तकनीकी समस्याओं की जानकारी पहले भी विभागीय अधिकारियों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद यदि केवल ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन जारी किया जाता है तो कई शिक्षकों का वेतन प्रभावित हो सकता है, जबकि उनकी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तकनीकी खामी इसकी वजह होगी। संदीप पाण्डेय ने कहा कि तकनीकी समस्याओं का समाधान किए बिना वेतन काटना या रोकना शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। इससे शिक्षकों का मनोबल भी प्रभावित होगा। उन्होंने मांग की कि जब तक वीएसके ऐप पूरी तरह सुचारू और त्रुटिरहित नहीं हो जाता, तब तक शिक्षकों का वेतन विद्यालय की उपस्थिति पंजी और प्रधान पाठक अथवा प्राचार्य द्वारा प्रमाणित वेतन देयक के आधार पर ही आहरित किया जाए। फेडरेशन ने यह भी मांग की है कि केवल तकनीकी कारणों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में किसी भी शिक्षक का वेतन न काटा जाए।

तालाब निर्माण में करोड़ों की कथित अनियमितता का मामला

तालाब पहली बारिश में बह गए, अब मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत

- गुणवत्ताहीन निर्माण, तकनीकी लापरवाही के आरोप
- JCB-ट्रैक्टर के उपयोग, फर्जी मस्टर रोल की शिकायत
- करोड़ों के सरकारी धन के दुरुपयोग की उच्चस्तरीय जांच की मांग

कोरिया जन सहयोग समिति ने डीएफओ के नाम सौंपा ज्ञापन, एसडीओ फॉरेस्ट ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन

गुणवत्ताहीन निर्माण,जेसीबी के उपयोग,फर्जी मस्टर रोल और सरकारी धन के दुरुपयोग की उच्चस्तरीय जांच की मांग

कोरिया जन सहयोग समिति ने खोला मोर्चा, डीएफओ के नाम ज्ञापन, एसडीओ फॉरेस्ट ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन

कोरिया वन मंडल के तालाब निर्माण में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप

राजन पाण्डेय

बैकुंठपुर (कोरिया),28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया वन मंडल के सोनहत वन परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा कराए गए तालाब निर्माण कार्यों को लेकर उठ रहे सवाल अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर शासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गए हैं,दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार प्रकाशित खोजी समाचारों के बाद अब कोरिया जन सहयोग समिति ने मुख्यमंत्री के नाम विस्तृत शिकायत भेजकर करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता,गुणवत्ताहीन निर्माण, तकनीकी लापरवाही,नियम विरुद्ध मशीनों के उपयोग,फर्जी मस्टर रोल और सरकारी धन के दुरुपयोग की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच की मांग की है,समिति का आरोप है कि जल संरक्षण और वन्यजीवों के हित में बनाए गए तालाबों का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं हुआ,जिसके कारण कई तालाब पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गए,शिकायत में पूरे प्रकरण की स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायत में लगाए गए प्रमुख आरोप

1. पहली ही बारिश में टूट गए तालाब,गुणवत्ता पर गंभीर सवाल- शिकायत में कहा गया है कि कई तालाब सामान्य वर्षा भी नहीं झेल पाए और उनकी पाल टूट गई,इससे यह आशंका व्यक्त की गई है कि निर्माण के दौरान मिट्टी का समुचित संघनन, निर्धारित गहराई,चौड़ाई,ऊंचाई तथा जल निकासी जैसे तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया,यदि यह आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह केवल निर्माण की तकनीकी विफलता नहीं बल्कि सरकारी धन के उपयोग की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करेगा।

2. मानसून में जेसीबी और ट्रैक्टर के उपयोग का आरोप- शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 15 जून के बाद भी, जब सामान्यतः मिट्टी से जुड़े कार्य प्रतिबंधित माने जाते हैं,तब जून और जुलाई में जेसीबी तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसी भारी मशीनों से खुदाई कराई गई,शिकायतकर्ताओं ने इसे शासन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की आशंका बताया है।

3. स्थानीय मजदूरों का रोजगार प्रभावित,फर्जी मस्टर रोल की आशंका- शिकायत में कहा गया है कि वन विभाग की योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराना है,इसके बावजूद मशीनों से कार्य कराए जाने के कारण स्थानीय श्रमिकों का रोजगार प्रभावित हुआ,साथ ही कागजों में फर्जी मस्टर रोल बनाकर सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका भी व्यक्त की गई है।

4. सूचना बोर्ड तक नहीं लगाए गए- समिति ने शिकायत में कहा है कि कई निर्माण स्थलों पर अनिवार्य सूचना पट्ट नहीं लगाए गए, इससे स्वीकृत राशि,कार्य एजेंसी,निर्माण की लागत,तकनीकी विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी।

5. ग्राम वन समितियों की उपेक्षा का आरोप- शिकायत के अनुसार ग्राम वन समितियों को निर्माण प्रक्रिया से दूर रखा गया तथा बिना समुचित भौतिक सत्यापन के भुगतान किए जाने की आशंका जताई गई है।

लगातार खबरों के बाद सामाजिक संगठन भी आए सामने

दैनिक घटती-घटना पिछले कई दिनों से वन विभाग के तालाब निर्माण को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है,समाचारों में निर्माण गुणवत्ता,मशीनों के उपयोग, तकनीकी मानकों की अनदेखी तथा पहली ही बारिश में तालाब टूटने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया,अब इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर कोरिया जन सहयोग समिति ने शासन को विस्तृत शिकायत भेजी है,शिकायत में प्रकाशित समाचारों का भी उल्लेख किया गया है।

डीएफओ के नाम ज्ञापन,एसडीओ फॉरेस्ट से हुई मुलाकात

वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) की अनुपस्थिति में समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उप वनमंडलाधिकारी (एसडीओ फॉरेस्ट) को ज्ञापन सौंपा,प्रतिनिधिमंडल ने निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने,दोषियों की जिम्मेदारी तय करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग रखी, समिति के अनुसार, एसडीओ फॉरेस्ट ने शिकायत के सभी बिंदुओं की जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पुष्पेंद्र राजवाड़े बोले...जनहित की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे...

समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि यदि जल संरक्षण जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार या तकनीकी लापरवाही होगी तो इसका नुकसान सीधे जनता और पर्यावरण को होगा, उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की।

जयचंद सोनपाकर की चेतावनी...जरूरत पड़ी तो होगा जनआंदोलन

कार्यकारी अध्यक्ष एवं अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर ने कहा कि यदि विभाग ने समयबद्ध और निष्पक्ष जांच नहीं कराई तो समिति न्यायालय जाने के साथ-साथ लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन भी करेगी। संजय साहू ने उठाया रोजगार का मुद्दा- कानूनी सलाहकार अधिवक्ता संजय साहू ने कहा कि यदि निर्माण कार्य मशीनों से कराए जा रहे हैं तो इससे स्थानीय मजदूरों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,उन्होंने नियमों के अनुरूप कार्य कराने और स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने की मांग की।

रजा अली अंसारी बोले...लीपापोती हुई तो न्यायालय जाएंगे...

वरिष्ठ अधिवक्ता रजा अली अंसारी ने कहा कि यदि शिकायत के बावजूद मामले में लीपापोती की गई या समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई, तो समिति न्यायालय सहित सभी वैधानिक विकल्पों का उपयोग करेगी।

ये रहे मौजूद...

ज्ञापन सौंपने के दौरान समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े,कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर,वरिष्ठ कानूनी सलाहकार रजा अली अंसारी,कानूनी सलाहकार अधिवक्ता अरविंद सिंह,अधिवक्ता संजय साहू,संरक्षक राजन पाण्डेय,उपाध्यक्ष राजू साहू एवं बालकरण सोनपाकर सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

अब निगाहें जांच और कार्रवाई पर...

वन विभाग के तालाब निर्माण को लेकर पहले मीडिया में सवाल उठे,फिर पहली बारिश में निर्माण की गुणवत्ता पर विवाद सामने आया और अब सामाजिक संगठन ने औपचारिक शिकायत के माध्यम से मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा दिया है,ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विभाग केवल जांच का आश्वासन देगा या शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा और यदि अनियमितताएं सिद्ध होती हैं तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी करेगा।

रविदास जयंती पर भाजपा का समरसता अभियान शुरू,विपक्ष पर भी साधा निशाना

प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी बोले...संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाएंगे सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बनाएंगे अभियान का आधार...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती को भाजपा इस बार केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखेगी,बल्कि इसे सामाजिक समरसता और वैचारिक अभियान के रूप में पूरे देश में चलाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं समरसता संकल्प अभियान के प्रदेश संयोजक अखिलेश सोनी ने सोमवार को संकल्प भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष माघ पूर्णिमा तक पार्टी देशभर में संत रविदास के जीवन, दर्शन और सामाजिक समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया,प्रदेश प्रवक्ता एवं संत रविदास जयंती कार्यक्रम के जिला प्रभारी संतोष दास,जिला महामंत्री विनोद हर्ष एवं अरुणा सिंह, गुरु पूर्णिमा जिला प्रभारी विद्यानंद

मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी रूपेश दुबे,जन्मेजय मिश्रा सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिलेश सोनी ने कहा कि भाजपा स्वयं को केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन मानती है। उनका कहना था कि पार्टी का मूल मंत्र 'राष्ट्र प्रथम' और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है। संत रविदास का जीवन सामाजिक भेदभाव मिटाने, समानता स्थापित करने और समाज को जोड़ने की प्रेरणा देता है। आज के समय में उनके विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हैं और भाजपा इन्हें समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

देशभर में चलेगा अभियान,कलश यात्रा और जनसंपर्क होंगे : उन्होंने बताया कि अभियान के तहत देशभर में कलश यात्राएं निकाली जाएंगी, छात्रावासों और सामाजिक संस्थाओं में संपर्क अभियान चलाया जाएगा तथा संत रविदास के जीवन-दर्शन पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा की टीम प्रदेश के सभी 36 संगठनात्मक जिलों का दौरा कर सामाजिक समरसता, संवेदनशीलता और समावेशिता का संदेश देगी।

विपक्ष पर लगाया समाज को बांटने का आरोप : पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश सोनी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक शक्तियां जाति और भेदभाव की राजनीति कर समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय, समान अवसर और समरसता के आधार पर समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मान और अवसर पहुंचाने की प्रतिबद्धता पर आधारित है।

सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं...

प्रदेश महामंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थों के विकास से लेकर समाज के वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने तक कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से राष्ट्रपति का चयन और विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के नेतृत्व को अवसर मिलना भाजपा की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संत रविदास के संदेश को समाज तक पहुंचाने का संकल्प

अखिलेश सोनी ने कहा कि संत रविदास केवल एक संत नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं। उनके विचार जाति, ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर समानता,सद्भाव और मानवता का संदेश देते हैं। भाजपा कार्यकर्ता आगामी एक वर्ष तक गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर उनके विचारों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

खेत में रोपा लगाने गए परिवार के घर चोरी, नकदी समेत जेवर और कांसे के बर्तन ले उड़े चोर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर में खेत में रोपा लगाने गए परिवार के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 50 हजार रुपए नकदी,जेवर,कांसे के बर्तन और अन्य सामान पार कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में शांति बाई ने बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती है। 24 जुलाई को उनका बेटा-बहू ग्राम लटोरी गए हुए थे, जबकि पति काम से लखनपुर गए थे। बेटी बकरी चराने चली गई थी। सुबह करीब 10 बजे वह अपने पोते विशाल के साथ घर में ताला लगाकर खेत में धान की रोपाई के लिए चली गई थी। शाम करीब 5 बजे जब वह घर लौटीं तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और पेटी खुली हुई थी। सामान की जांच करने पर पता चला कि अज्ञात चोर घर से 50 हजार रुपए नकद,एक जोड़ी चांदी की पायल,सोने की फुल्ली, कांसे की 2 थालियां,4 लोटे और 12 कटोरियां, 10 साड़ियां तथा मतदाता पहचान पत्र चोरी कर ले गए हैं। पीड़िता ने आसपास के लोगों से पूछताछ की,लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

कथित ऑडियो,शिकायत और चार साल की चुप्पी...क्या अब आईजी दिलाएंगे जवाब?

प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी का कथित ऑडियो फिर चर्चा में...चार साल पुरानी शिकायत पर जवाब अब भी बाकी

शिकायत,कथित ऑडियो और चार साल की खामोशी...आखिर किसकी मेहरबानी से नहीं खुली जांच की फाइल?

कथित वायरल ऑडियो ने फिर उठाए सवाल,क्या शिकायत फाइलों में दफन हो गई?

ऑडियो वायरल,शिकायत दर्ज,फिर भी कार्रवाई का अता-पता नहीं...क्या जवाबदेही सिर्फ आम नागरिकों के लिए है?

चार साल पहले उठे सवाल आज भी कायम,क्या पुलिस अपने ही कर्मचारी की शिकायत भूल गई?

क्या वर्दी का मतलब जवाबदेही से ऊपर होना है? चार साल पुराने कथित ऑडियो ने फिर खड़े किए सवाल

प्रधान आरक्षक पर लगे आरोपों की जांच हुई या नहीं? चार साल बाद फिर वायरल हुआ कथित ऑडियो ने उठाया सवाल

शिकायत हुई,बयान हुए,कथित ऑडियो भी मिला...फिर कार्रवाई किस मोड़ पर रुक गई?

दिसंबर 2021 में पुलिस अधीक्षक को शिकायत और कथित ऑडियो सौंपे जाने का दावा

चार साल बाद फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने से उठे सवाल–यदि जांच हुई थी तो उसका परिणाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? यदि नहीं हुई, तो जिम्मेदारी किसकी है?

रवि सिंह

कोरिया/एमसीबी,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

न्याय व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ पुलिस मानी जाती है,आम नागरिक जब किसी अन्याय, अपराध,धमकी या विवाद का सामना करता है तो सबसे पहले पुलिस के दरवाजे पर ही दस्तक देता है,लेकिन जब शिकायत का केंद्र स्वयं पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी बन जाए, शिकायत के साथ कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो,आवेदन पुलिस अधीक्षक तक पहुंच जाए और उसके बाद भी वर्षों तक यह स्पष्ट न हो कि कार्रवाई हुई या नहीं,तब सवाल केवल एक कर्मचारी पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर खड़े होते हैं, कोरिया जिले में एक बार फिर ऐसा ही मामला चर्चा में है,करीब चार वर्ष पुराना बताया जा रहा एक कथित ऑडियो फिर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों में वायरल हो रहा है,दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में वर्तमान में एमसीबी जिले में पदस्थ का एक प्रधान आरक्षक एक युवक से मोबाइल पर बातचीत के दौरान पैसे की मांग करता,अभद्र भाषा का प्रयोग करता और कथित रूप से धमकी देता सुनाई देता है,इस ऑडियो की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन यह भी तथ्य सामने है कि दिसंबर 2021 में इसी कथित ऑडियो के साथ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी गई थी,अब प्रश्न यह नहीं रह गया कि ऑडियो पुराना है या नया। असली प्रश्न यह है कि यदि शिकायत हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ? यह समाचार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं है,यह उन सवालों को सामने रखने का प्रयास है जो चार वर्षों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिकायत हुई, कथित ऑडियो जमा हुआ,आरोप लगे,चर्चा हुई,समाचार प्रकाशित हुए–लेकिन जनता आज भी यह नहीं जानती कि निष्कर्ष क्या निकला,कानून का शासन केवल अपराधियों पर कार्रवाई से नहीं,बल्कि अपने तंत्र की निष्पक्ष जांच से भी स्थापित होता है,यदि शिकायत निराधार थी,तो उसका स्पष्ट निष्कर्ष सामने आना चाहिए,यदि शिकायत में तथ्य थे,तो कार्रवाई भी दिखनी चाहिए,वर्दी का सबसे बड़ा सम्मान कार्रवाई से नहीं,बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई से मिलता है। और जवाबदेही से बड़ी कोई वर्दी नहीं होती।

चार साल बाद फिर वही ऑडियो, फिर वही सवाल-समय बीत गया,अधिकारी बदले,पदस्थापनाएं बदलीं,लेकिन सवाल वहीं के वहीं रह गए,अब जब यही कथित ऑडियो फिर व्हाट्सएप समूहों में वायरल हो रहा है तो लोगों के बीच चर्चा है कि क्या चार साल पहले दी गई शिकायत पर कोई निष्कर्ष निकला था? यदि निकला था,तो जनता को क्यों नहीं बताया गया? यदि नहीं निकला, तो आखिर किस कारण से?

शिकायत केवल कागज नहीं थी...उसके साथ कथित ऑडियो भी था...

दिसंबर 2021 में पुलिस अधीक्षक,कोरिया को दिए गए आवेदन में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संबंधित प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी उससे आर्थिक लेन-देन को लेकर लगातार संपर्क कर रहा था,शिकायत में दावा किया गया कि फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया,पैसे नहीं देने पर धमकी दी गई और अपने पद का प्रभाव दिखाने की कोशिश की गई, शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उसके पास बातचीत की रिकॉर्डिंग है और उसने वही रिकॉर्डिंग पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराई,सामान्य परिस्थितियों में किसी भी विभाग के लिए यह पर्याप्त आधार होता है कि वह प्रारंभिक जांच शुरू करे, दोनों पक्षों के बयान ले,तकनीकी परीक्षण कराए और तथ्य सामने लाए,लेकिन चार वर्ष बाद भी जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि उस शिकायत की जांच आखिर किस मुकाम तक पहुंची?

क्या जांच हुई थी या केवल फाइल चलती रही?

सरकारी व्यवस्था में हर शिकायत की एक यात्रा होती है,आवेदन आता है,डायरी में दर्ज होता है, जांच अधिकारी नियुक्त होता है,बयान दर्ज होते हैं, रिपोर्ट बनती है, फिर कार्रवाई होती है,लेकिन इस मामले में लोग पूछ रहे हैं कि यह यात्रा आखिर कहां जाकर रुक गई? क्या जांच शुरू ही नहीं हुई? क्या जांच हुई लेकिन पूरी नहीं हुई? क्या जांच पूरी हुई लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई? या फिर शिकायत किसी फाइल में दबकर रह गई?

कथित ऑडियो की वैज्ञानिक जांच हुई या नहीं?-आज तकनीक इतनी विकसित है कि किसी भी ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कर यह पता लगाया जा सकता है कि उसमें छेड़छाड़ हुई है या नहीं,आवाज किसकी है और रिकॉर्डिंग में संपादन हुआ या नहीं,यदि दिसंबर 2021 में शिकायत के साथ ऑडियो उपलब्ध कराया गया था,तो क्या उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया? यदि भेजा गया तो रिपोर्ट क्या कहती है? यदि नहीं भेजा गया तो क्यों नहीं भेजा गया? इन सवालों का जवाब केवल विभाग ही दे सकता है।

शिकायतकर्ता ने लगाए थे और भी गंभीर आरोप- पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि संबंधित प्रधान आरक्षक का कथित रूप से जुआ फड़ संचालकों से संपर्क है और आर्थिक लेन-देन को लेकर दबाव बनाया जाता है, ये आरोप गंभीर थे,लेकिन आरोप और तथ्य में अंतर होता है, यही कारण है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच सबसे आवश्यक होती है, यदि आरोप गलत थे तो संबंधित कर्मचारी को स्पष्ट रूप से राहत मिलनी चाहिए थी,यदि आरोप सही थे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी,लेकिन जब दोनों में से किसी का परिणाम सार्वजनिक नहीं होता,तब सवाल व्यवस्था पर उठते हैं।

क्या संरक्षण की चर्चा यूं ही होती है?- स्थानीय स्तर पर लंबे समय से यह चर्चा रही है कि संबंधित प्रधान आरक्षक का नाम कई विवादों में आया, लेकिन उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं हुई,यह चर्चा सत्य है या नहीं, इसका निष्कर्ष बिना जांच नहीं निकाला जा सकता,लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है कि ऐसी धारणा बनी क्यों? क्या विभाग ने समय रहते पारदर्शी कार्रवाई कर इन चर्चाओं को समाप्त करने का प्रयास किया? यदि नहीं किया, तो ऐसी चर्चाएं स्वाभाविक रूप से जन्म लेती हैं।

चार महीने का तबादला और फिर वापसी-सिर्फ संयोग या सामान्य प्रक्रिया?- स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जाता है कि शिकायतों के बाद संबंधित प्रधान आरक्षक का कुछ समय के लिए जशपुर स्थानांतरण हुआ और बाद में उसकी वापसी एमसीबी जिला भी हो गई,यदि ऐसा हुआ, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया थी या शिकायत से जुड़ी कार्रवाई का हिस्सा,क्योंकि तबादला और अनुशासनात्मक कार्रवाई दोनों अलग-अलग विषय हैं।

दैनिक घटती-घटना ने पहले भी उठाया था यह मामला- यह विषय नया नहीं है, दैनिक घटती-घटना ने वर्ष 2022 में भी शिकायत और कथित ऑडियो के आधार पर यह प्रश्न उठाया था कि क्या विभाग कार्रवाई करेगा? आज चार साल बाद वही कथित ऑडियो फिर सामने आया है,ऐसे में इस प्रश्न को फिर उठाना किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना नहीं,बल्कि यह जानना है कि उस शिकायत का अंतिम परिणाम क्या हुआ, पत्रकारिता का दायित्व केवल खबर प्रकाशित करना नहीं,बल्कि उसके निष्कर्ष तक समाज को पहुंचाना भी है।

क्या वर्दी सवालों से बड़ी हो गई?- यह इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है,वर्दी सम्मान का प्रतीक है,लेकिन वर्दी सम्मान तभी तक है जब तक उसके साथ जवाबदेही भी जुड़ी रहे,यदि किसी आम नागरिक पर आरोप लगता है तो पुलिस तत्काल जांच करती है, लेकिन यदि आरोप किसी पुलिस कर्मचारी पर लगे हों,तो क्या जांच की गति बदल जानी चाहिए? क्या विभाग के भीतर जवाबदेही के मानदंड अलग होने चाहिए? क्या एक शिकायत केवल इसलिए महत्व खो देती है क्योंकि उसका संबंध विभाग के अपने कर्मचारी से है? यही वे प्रश्न हैं जो इस पूरे प्रकरण को सामान्य विवाद से आगे ले जाकर संस्थागत जवाबदेही का विषय बना देते हैं।

अब निगाहें आईजी पर- चूंकि मामला फिर चर्चा में आया है, इसलिए अब सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि यदि शिकायत और रिकॉर्ड उपलब्ध हैं,तो उनकी समीक्षा कराई जाए, यदि जांच पूरी हो चुकी है,तो उसका निष्कर्ष सार्वजनिक किया जाए, यदि जांच अधूरी है, तो उसे पूरा कराया जाए,यदि ऑडियो की तकनीकी जांच नहीं हुई थी,तो अब कराई जाए,इससे न केवल सच्चाई सामने आएगी,बल्कि पुलिस विभाग पर जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

एक सवाल जो हर नागरिक पूछ रहा है, यदि शिकायतकर्ता के आरोप सही हैं और यदि कथित ऑडियो वास्तविक है,तो एक सीधा सवाल उठता है...

- आखिर एक पुलिस कर्मचारी किसी नागरिक से पैसे क्यों मांगेगा?
- यदि यह निजी लेन-देन था, तो उसकी वास्तविक प्रकृति क्या थी?
- यदि यह निजी विवाद नहीं था, तो शिकायतकर्ता ने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए?
- यदि शिकायत झूठी थी, तो क्या उसे झूठा साबित करने वाली जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई?
- और यदि शिकायत में दम था, तो कार्रवाई कहां हुई?

इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

चार साल बाद भी जिन सवालों का जवाब बाकी है...

- दिसंबर 2021 की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई?
- क्या कथित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच हुई?
- क्या संबंधित प्रधान आरक्षक और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हुए?
- क्या विभागीय जांच पूरी हुई?
- जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई?
- यदि शिकायत गलत थी, तो शिकायतकर्ता पर क्या कार्रवाई हुई?
- यदि शिकायत सही थी, तो संबंधित कर्मचारी पर क्या कार्रवाई हुई?
- क्या अब वायरल ऑडियो के बाद मामले की पुनः समीक्षा होगी?

10 माह बाद भी नहीं हुई कार्रवाई,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने संविदा भर्ती घोटाले की जांच की मांग दोहराई

मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव और कलेक्टर को भेजा पुनः स्मरण पत्र; भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर पारदर्शी तरीके से दोबारा नियुक्ति कराने की मांग

-संवाददाता-

एमसीबी/बैकुण्ठपुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में हुई संविदा भर्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर एक बार फिर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (महिला एवं बाल विकास विभाग) तथा कलेक्टर, एमसीबी को स्मरण पत्र भेजा है,उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत किए जाने के लगभग 10 माह बीत जाने के बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, पूर्व विधायक ने अपने स्मरण पत्र में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, विवादित भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर पारदर्शी तरीके से पुनः भर्ती कराने तथा अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार तत्कालीन नियुक्तिकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

इन भर्तियों की जांच की मांग- गुलाब कमरो ने जिन संविदा भर्तियों की जांच की मांग की है, उनमें शामिल हैं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की संविदा भर्ती, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन की राज्य एवं जिला स्तरीय संविदा भर्ती, मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु की गई संविदा भर्ती,महिला संरक्षण अधिकारी की संविदा नियुक्ति, सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन के लिए सेवा प्रदाताओं की संविदा भर्ती।

10 माह बाद भी कार्रवाई नहीं, प्रशासन पर उठ रहे सवाल- पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि शिकायत किए जाने के लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि इस देरी से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं, उन्होंने मांग की कि यदि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कठोर कार्रवाई की जाए तथा पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त कर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुनः भर्ती कराई जाए, कमरो ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से ही योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा और शासन की योजनाओं के प्रति लोगों का विश्वास भी बना रहेगा।

कोरिया में गौ सम्मान अभियान के दूसरे चरण के तहत जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन

गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन जारी,मांगें पूरी नहीं होने पर जंतर-मंतर में अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर/कोरिया,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

गौ सम्मान अभियान के तहत सोमवार को अभियान के दूसरे चरण में कोरिया जिले के कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री एवं शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चलाया जा रहा है,जिसका उद्देश्य गोहत्या-निषेध के लिए केंद्रीय कानून, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा तथा गो संरक्षण से संबंधित अन्य मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। अभियान के प्रतिनिधी रेवा यादव ने बताया कि पहले चरण में तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा जा चुका है,जबकि दूसरे चरण में जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है,उन्होंने बताया कि आगामी चरणों में क्रमशः संभागीय आयुक्त (कमिश्नर), मुख्यमंत्री,राज्यपाल, प्रधानमंत्री और अंत में राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा जाएगा,अभियान के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि इन सभी चरणों के बाद भी गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने सहित प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है,तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर में अनिश्चितकालीन धरना और अनशन शुरू किया जाएगा, अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किया जा रहा है। उनका कहना है कि देशभर के करोड़ों नागरिकों का समर्थन इस अभियान को मिल रहा है और सरकार से जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने की अपेक्षा की जा रही है, इस अवसर पर अभियान से जुड़े पदाधिकारी, संत-महात्मा, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गौभक्त उपस्थित रहे।

विकास के नक्शे से गायब रेवला,जंगलों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार

अमृतकाल के दावों के बीच रेवला की हकीकत,न सड़क,न स्कूल,न बिजली, न पानी

मोबाइल टावर खड़ा,नेटवर्क गायब;पाइपलाइन बिछी,पानी नहीं...यही है रेवला की कहानी

अंधेरे,प्यास और बदहाल रास्तों के बीच जी रहा रेवला, आखिर कब जागेगा सिस्टम?

जहां बच्चे हैं,लेकिन स्कूल नहीं...विकास की राह अब भी देख रहा रेवला

देश अमृतकाल मना रहा,रेवला अब भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम

विशेष पिछड़ी जनजाति का गांव, लेकिन विकास से सबसे ज्यादा दूर रेवला

बच्चे हैं, लेकिन स्कूल नहीं...सड़क नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं; विशेष पिछड़ी जनजाति के इस गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार

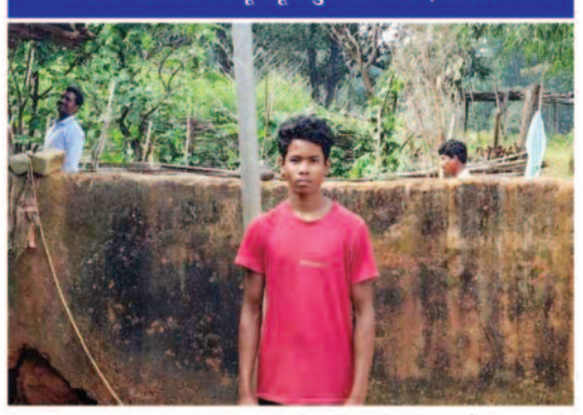

कोरिया/सोनहत,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

देश आज़ादी के अमृतकाल का उत्सव मना रहा है,प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं,गांव-गांव तक सड़क,बिजली,नल-जल, शिक्षा,स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं,सरकारी विज्ञापनों में विकास की तस्वीर चमकती नजर आती है,लेकिन यदि इन दावों की हकीकत देखनी हो तो कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के सुदूर वनांचल में बसे रेवला गांव तक पहुंचना होगा,यहां पहुंचते ही सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला साफ दिखाई देता है,घने जंगल,ऊंचे पहाड़ और पगडंडियों के बीच बसे इस छोटे से गांव में करीब 50 से अधिक लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के बिना जीवन जीने को मजबूर हैं,गांव में सड़क नहीं, बिजली नहीं,शुद्ध पेयजल नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं,स्वास्थ्य सुविधा नहीं और सबसे बड़ी विडंबना यह कि करीब 15 बच्चे होने के बावजूद गांव में एक भी स्कूल नहीं है,गांव में प्रवेश करते ही ग्रामीणों का एक ही सवाल सुनाई देता है साहब...हम भी छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं...फिर हमारी इतनी अनदेखी क्यों? यह सवाल केवल किसी सरकार से नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र से है।

क्या सरगुजा संभाग का पहला स्कूल विहीन गांव है रेवला?

रेवला की सबसे बड़ी पीड़ा शिक्षा है, गांव में लगभग 15 स्कूली बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है,विडंबना यह है कि विकासखंड में ऐसे कई स्कूल संचालित हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या दस से भी कम है,लेकिन रेवला आज भी स्कूल का इंतजार कर रहा है,सबसे निकट का प्राथमिक विद्यालय मेण्ड्रा में है,जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है, पंचायत मुख्यालय कछाड़ी करीब 35 किलोमीटर दूर पड़ता है,ऐसे में ग्रामीण मजबूरी में बच्चों को मेण्ड्रा,सोनहत और तेलीमुड़ा की आश्रम शालाओं में भेजते हैं,एक ग्रामीण महिला भावुक होकर कहती है बच्चा बीमार हो जाए या उससे मिलने जाना हो,पूरा दिन लग जाता है...हमारे गांव में भी अगर एक छोटा-सा स्कूल होता तो शायद बच्चों का बचपन हमारे सामने बीतता।

यहां बीमार होना मतलब मौत से लड़ना...

रेवला में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है, गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, जब कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है या किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो ग्रामीण मरीज को खाट पर लिटाकर कई किलोमीटर तक पहाड़ और जंगल पार कर मुख्य सड़क तक ले जाते हैं,इसके बाद ही एम्बुलेंस मिलती है,अर्थात जिस समय मरीज को अस्पताल में होना चाहिए,उस समय वह जंगल के रास्ते जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा होता है, ग्रामीण बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की चिरायु टीम कभी-कभार आती है,लेकिन नियमित स्वास्थ्य सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं है।

जल जीवन मिशन पहुंचा... लेकिन पानी नहीं...

रेवला में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन जरूर दिखाई देती है,लेकिन पानी आज तक नहीं आया,ग्रामीण बताते हैं कि पाइप तो बिछा दिए गए, लेकिन न टंकी बनी,न बोरिंग हुई और न जलापूर्ति शुरू हुई, गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है,ऐसे में पूरा गांव आज भी नाले का पानी पीने को मजबूर है,बरसात के दौरान यही पानी गंदगी से भर जाता है, जिससे मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है।

धान उगाते हैं...लेकिन बेच नहीं पाते...

रेवला के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं, वे धान तो उगाते हैं,लेकिन सड़क नहीं होने के कारण उपज को सहकारी समिति तक नहीं पहुंचा पाते,कई किसानों का किसान पंजीयन नहीं हो पाया है,केसीसी और खाद-बीज जैसी सुविधाओं का लाभ भी सीमित है, ग्रामीण बताते हैं कि पटवारी केवल गिरदावरी के समय आते हैं, इसके अलावा शायद ही कोई अधिकारी गांव तक पहुंचता हो।

मोबाइल टावर बना...नेटवर्क आज तक नहीं...

डिजिटल इंडिया के दौर में भी रेवला संचार व्यवस्था से लगभग कटा हुआ है,ग्रामीण बताते हैं कि पिछली सरकार के दौरान बीएसएनएल का टावर लगाया गया,निर्माण पूरा हुआ,मशीनें भी लग गईं,लेकिन आज तक नेटवर्क चालू नहीं हुआ,टावर खड़ा है,लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आता।

अंधेरे में गुजरती हर रात-जब शहरों और गांवों में शाम होते ही बिजली की रोशनी फैल जाती है, तब रेवला अंधेरे में डूब जाता है, गांव में न बिजली है और न ही कोई स्थायी सौर ऊर्जा व्यवस्था, करीब पांच वर्ष पहले क्रेडा द्वारा कुछ सोलर होम लाइटें दी गई थीं, लेकिन अधिकांश अब खराब हो चुकी हैं, आज भी ग्रामीण ढिबरी,दीया और टॉर्च के सहारे रात बिताते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, महिलाएं अंधेरे में भोजन बनाती हैं, बीमार व्यक्ति का इलाज भी टिमटिमाती रोशनी में होता है,यह केवल बिजली का अंधेरा नहीं, बल्कि विकास की रोशनी से दूर छूटे एक गांव की तस्वीर है।

विशेष पिछड़ी जनजाति का गांव, फिर भी सबसे ज्यादा उपेक्षित-रेवला में मुख्य रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो और चेरवा समाज के लोग रहते हैं, पंडो जनजाति को विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले समुदाय के रूप में जाना जाता है, सरकारें इनके विकास के लिए विशेष योजनाओं और पैकेजों की घोषणा करती रही हैं,लेकिन रेवला की तस्वीर उन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है,जब विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग भी ड़क,बिजली,पानी,शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हों, तब योजनाओं की जमीनी स्थिति पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं।

ग्रामीणों की सिर्फ एक मांग-पहले सड़क बनाइए...

रेवला के लोगों की मांग बहुत बड़ी नहीं है, वे कहते हैं पहले सड़क बना दीजिए,सड़क होगी तो–एम्बुलेंस आएगी,बच्चे स्कूल जाएंगे, किसान धान बेच पाएंगे, बिजली पहुंचेगी,पानी पहुंचेगा,स्वास्थ्य सेवाएं आएंगी,विकास अपने आप पहुंच जाएगा।

आखिर कब सुनेगा सिस्टम?

रेवला केवल एक गांव नहीं, बल्कि उन तमाम वनांचल गांवों का प्रतीक है जो आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं, जब पूरा देश अमृतकाल की उपलब्धियों का जश्न मना रहा है,तब रेवला के लोग आज भी एक सड़क, एक स्कूल,एक हैंडपंप और एक बिजली के खंभे का इंतजार कर रहे हैं,यह ग्राउंड रिपोर्ट केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उस सवाल की पड़ताल है जिसका जवाब शायद व्यवस्था के पास अभी भी नहीं है क्या इन ग्रामीणों का कसूर सिर्फ इतना है कि उनका जन्म जंगलों के बीच बसे एक दूरस्थ गांव में हुआ? और रेवला के हर घर से आज भी एक ही आवाज निकलती है– साहब...हम भी छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं...फिर हमारी इतनी अनदेखी क्यों?

मौत बनकर गिरी आसमानी बिजली,एमसीबी में 3 की दर्दनाक मौत

खड़गवां के शिवपुर और मंगोरा गांव में गाज गिरने से 5 लोग घायल,लगातार बारिश के बीच बढ़ा खतरा

-संवाददाता-
खड़गवां/एमसीबी,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

लगातार हो रही बारिश के बीच मंगलवार को एमसीबी जिले में आकाशीय बिजली ने भीषण कहर बरपाया,खड़गवां विकासखंड के शिवपुर और मंगोरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई,जबकि पांच लोग घायल हो गए,इस हृदयविदारक घटना के बाद दोनों गांवों सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिवपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई,वहीं मंगोरा गांव में गाज गिरने से एक अन्य व्यक्ति की जान चली गई, हादसे में घायल हुए पांच लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा-घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची,अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतकों के शवों का पंचनामा तैयार कराया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया,प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा मृतकों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। लगातार बारिश के बीच बढ़ा आकाशीय बिजली का खतरा-एमसीबी जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है,मौसम विभाग द्वारा भी खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई जाती रही है,ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों,खेतों,ऊंचे पेड़ों तथा बिजली के खंभों के पास जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। गांवों में पसरा मातम-इस हादसे के बाद शिवपुर, मंगोरा और आसपास के गांवों में मातम का माहौल है,जनप्रतिनिधियों,सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

कॉमनवेल्थ गेम्स में छत्तीसगढ़ की बेटी का कमाल,ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक

डीआईजी-एसएसपी राजेश अग्रवाल ने वीडियो कॉल पर दी बधाई...

कहा...यह उपलब्धि पूरे पुलिस परिवार और प्रदेश के लिए गर्व का क्षण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 (कॉमनवेल्थ गेम्स) में छत्तीसगढ़ की अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक एवं छत्तीसगढ़ पुलिस की सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 53 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि पर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रतियोगिता के स्नैच वर्ग में 88 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्क में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 111 किलोग्राम वजन उठाया।

कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया और भारत के लिए रजत पदक अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने वीडियो कॉल के जरिए ज्ञानेश्वरी यादव से सीधे संवाद किया। उन्होंने सरगुजा पुलिस एवं समस्त छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार की ओर से उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पुलिस सेवा में रहते हुए अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना अत्यंत गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने अनुशासन, समर्पण और कठोर परिश्रम से यह साबित किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की यह सफलता केवल छत्तीसगढ़ पुलिस ही नहीं,बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं,खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे भविष्य की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करती रहेंगी। ज्ञानेश्वरी यादव की इस उपलब्धि पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और खेल जगत से जुड़े लोगों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

चेन्नई लव स्टोरी ने तोड़ा रिकॉर्ड, बनी किरण अब्बावरम की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

किरण अब्बावरम की फिल्म चेन्नई लव स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। फिल्म की कहानी को फैंस पसंद कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं। किरण अब्बावरम ने तीन दिन में शानदार कलेक्शन कर लिया है। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर लिमिटेड बज था, लेकिन रिलीज के साथ फिल्म ने धमाका कर दिया है।

सैक्निल्क के मुताबिक,फिल्म ने पहले दिन 4.95 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म को 1638 शोज़ मिले और फिल्म को 41 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली। दूसरे दिन फिल्म ने 5.75 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म को 1762 शोज़ मिले और फिल्म को 50 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली। तीसरे दिन फिल्म ने 6.50 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म को तीसरे दिन 1851 शोज़ मिले और 58 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली। इसी के साथ फिल्म ने टोटल 17.20 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।वर्ल्ड वाइड फिल्म के कलेक्शन पर नज़र डालें तो फिल्म ने दुनियाभर में 42.87 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में टोटल 5 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसी के साथ फिल्म किरण अब्बावरम की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है। फिल्म ने एसआर कल्याणमंडपम को पछाड़ दिया है। एसआर कल्याणमंडपम ने 11.17 करोड़ की कमाई की थी।कोइमोई के मुताबिक, फिल्म 30 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म ने 50 परसेंट से ज्यादा का बजट रिकवर कर लिया है। अभी फिल्म को सेफ ज़ोन में जाने के लिए 12.8 करोड़ की कमाई की जरूरत है।बता दें कि फिल्म को रवि नंबू री ने डायरेक्ट किया है। वहीं फिल्म को श्रीनिवास कुमार और साई राजेश ने मास मूवी मेकर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म का म्यूजिक मणि शर्मा ने कंपोज किया है। फिल्म में किरण अब्बावरम और साई गौरी प्रिया लीड रोल में हैं। यह एक रोमांस ड्रामा है। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे है। फिल्म को फैंस पसंद कर रहे हैं। इसे रिव्यूज़ भी ठीक मिले हैं और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को फायदा हो रहा है।

31 साल बाद ममता कुलकर्णी के कल्ट गाने का बना रीमेक

अलका-ईला ने दी आवाज,नया वर्जन सुन राणा जी भी नहीं करेंगे माफ!

पुराने गानों के रीमेक के चलन के बीच, ममता कुलकर्णी के आइकॉनिक गाने का 31 साल बाद नया वर्जन आया है। इसे सुनने के बाद शायद राणा जी भी मेकर्स को माफ ना कर पाएं।

आजकल संगीत की दुनिया में पुराने गीतों को रीमेक करने का चलन चल पड़ा है। शायद ही ऐसा होता होगा कि किसी कल्ट या आइकॉनिक गाने का रीमेक ना बना हो। हालांकि हर बार ये फॉर्मूला हिट हो, ऐसा कतई नहीं है। अबतक कई गानों का रीमेक वर्जन बना है, लेकिन वो गाने हिट नहीं हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही हिट गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका हाल ही में रीमेक वर्जन आया है।

ममता कुलकर्णी के कल्ट गाने का बना रीमेक

दरअसल जिस कल्ट गाने की हम बात कर रहे हैं वह गाना साल 1995 में आई राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन का है और गाने का नाम है गुपचुप गुपचुप। जी हां, साल 1995 में सलमान खान, शाह रुख खान, ममता कुलकर्णी और काजोल की इस फिल्म का

यह गाना आज भी आइकॉनिक है। हर पार्टी की जान ये गाना कहा जाता है।

चाहे शादी हो या फिर कोई फंक्शन राणा जी माफ करना गाना बजता हुआ नजर आ ही जाता है। इस गाने में मतता कुलकर्णी नजर आई थीं और गाने में ममता कुलकर्णी ने ऐसी आग लगाई, जो आज भी फैंस के दिलों में जल रही है।

गाने को अलका याग्निक ने आवाज दी थी। वहीं अलका के साथ इसे ईला अरुण ने भी अपनी आवाज से सजाया था। गाने का संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया था और इसे इंदीवर ने लिखा था। अब करीब 31 साल बाद इस गाने का रीमेक आया है।

कैसा है गाने का रीमेक वर्जन?

गाने के नए रीमेक वर्जन को राणा जी 2.0 के नाम से रिलीज किया गया है। गाने में बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा नजर आई हैं। इस बात में कोई शक नहीं हैं कि माहिरा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। माहिरा ने अपनी तरफ से पूरी जान डाली है। गाने का संगीत इस बार तनिष्क बागची ने तैयार किया है। वहीं गाने में ओरिजिनल आवाज अलका याग्निक और ईला अरुण की ही रखी गई है। हालांकि सुनने पर ऐसा लगता है कि अलका ने इसे दोबारा से गाया भी है। गाने को डायरेक्ट और कॉरियोग्राफ रेमो डिसूजा ने किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर जबसे यह गाना आया है, इसे ट्रोल भी किया जा रहा है। लोगों को यह गाना पसंद नहीं आया है। गाने में बीट्स के साथ इसे नए तरीके से पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने जिन्होंने इसकी तारीफ की है,लेकिन उससे ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इसे लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि आखिरकार अच्छे भले गाने को खराब करने की जरूरत क्या थी। ऐसे कई रिएक्शन्स हैं,जो वायरल हो रहे हैं। अब इसे गाने को आप खुद सुनिए और तय कीजिए कि क्या वाकई में इस गाने का रीमेक बनना चाहिए था या नहीं।

ना पत्नी मिली ना गर्लफेंड,एयरहोस्टेस पर फिदा हुए फिरोज खान

आखिर में अकेला रह गया 80 दशक का सुपरस्टार

अपने जमाने के सबसे हैंडसम हीरोज में से एक फिरोज खान ने रॉयल एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगीर के लिए अपनी पत्नी सुंदरी खान को छोड़ दिया था। धर्मात्मा,कुरबानी और जानबाज जैसी फिल्मों के लिए मशहूर बॉलीवुड के ओरिजिनल काउबॉय फिरोज खान की मुलाकात 1960 के दशक की शुरुआत में एक पार्टी में सुंदरी से हुई थी। सुंदरी अपनी पहली शादी से अलग हो चुकी थीं और उनकी एक बेटी, सोनिया थी। फिरोज खान को उनसे पहली ही नजर में प्यार हो गया।दोनों ने पांच साल तक एक-दूसरे को डेट किया और 1965 में शादी कर ली। उनके दो बच्चे हुए -1970 में बेटी लैला और 1974 में बेटा फरदीन खान। उनका परिवार खुशहाल था। फिर फिरोज खान काम के सिलसिले में बैंगलोर चले गए।

बैंगलोर में ज्योतिका से हुई मुलाकात

बैंगलोर में उनकी मुलाकात हैदराबाद के एक शाही परिवार की सदस्य और एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगीर से हुई,जो राजा महेंद्रगीर धनराजगीर की बेटी थीं। वह उन पर पूरी तरह फिदा हो गए। चूंकि ज्योतिका बैंगलोर में रहती थीं और फिरोज भी मूल रूप से वहीं के रहने वाले थे,इसलिए वह काम के बहाने अक्सर मुंबई से दूर रहने लगे और अपना ज्यादातर समय ज्योतिका के साथ बिताने लगे, जबकि मुंबई में उनकी पत्नी और बच्चों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुंदरी को इस अफेयर के बारे में पता चलने से पहले यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा।

सुंदरी ने रातों-रात छोड़ा था घर

जब सुंदरी को इस अफेयर के बारे में पता चला,तो उन्होंने बिना कोई देर किए रातों रात अपना सामान पैक किया और फिरोज का घर छोड़ दिया। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं कह सकती हूं कि मैं तभी आजाद हो पाई जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। यह फैसला मैंने रातों-रात लिया। मैंने अपना सामान बांधा और नीचे रहने चली गई। उन्होंने आगे बताया,फिरोज और मैं एक ही घर में रहते थे;फर्क बस इतना था कि वह ज्यादातर समय बैंगलोर में अपनी नई साथी के साथ बिताते थे। उस इमोशनल उथल-पुथल और अकेलेपन से उबरने में मुझे लगभग एक साल लग गया। मुझे एक पत्नी के तौर पर बिताई जिंदगी की याद तो आती थी, लेकिन मिसेज खान वाली जिंदगी की नहीं।

जब ज्योतिका ने छोड़ा साथ

ज्योतिका ने फिरोज से कई बार शादी करने के लिए कहा। वह हमेशा यही कहते रहे कि जैसा चल रहा है,उसमें वह खुश है और चीजों को और उलझाना नहीं चाहते। ज्योतिका इंतजार करती रही,लेकिन वह बात टालते रहे। सालों तक साथ रहने और किसी पक्के वादे का इंतजार करने के बाद ज्योतिका ने फैसला कर लिया। उसने रिश्ता खत्म कर दिया और विदेश चली गई।

जब मुंबई वापस लौटे फिरोज खान

ज्योतिका के जाने के बाद, फिरोज मुंबई में अपने घर लौट आए। उन्होंने वहां बसने और सुंदरी के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने

की कोशिश की,मानो पिछले कुछ साल गुजरे ही न हों। लेकिन सुंदरी ने अपनी जिंदगी को आजाद तौर पर फिर से बनाने में कई साल बिताए थे। अब उन्हें अपनी पहचान के लिए मिसेज खान कहलाने की जरूरत नहीं थी।

फिरोज और सुंदरी का हुआ तलाक

20 साल की शादी के बाद,1985 में फिरोज और सुंदरी का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। सुंदरी ने अपने बच्चों की परवरिश ज्यादातर अकेले ही की। उनके बेटे फरदीन खान बॉलीवुड एक्टर बने; उन्होंने 1990 के दशक के आखिर में डेब्यू किया और बाद में नो एंट्री और जानशीन जैसी फिल्मों के लिए पहचाने गए।

बैंगलोर में हुआ फिरोज खान का निधन

फिरोज खान ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल बैंगलोर में बिताए, वही शहर जहां उनकी मुलाकात ज्योतिका से हुई थी और जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उन्होंने इस अफेयर के बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। वे आखिर तक इससे इनकार करते रहे। फिरोज खान का 27 अप्रैल 2009 को 69 साल की उम्र में बैंगलोर में कैंसर से निधन हो गया।

ऋषभ शेट्टी की द प्राइड ऑफ भारत से जुड़ीं भूमि पेडनेकर, वीर योद्धा रानी बेलावड़ी मल्लम्मा की किरदार से मचाएंगी तहलका

ऋषभ शेट्टी अपनी आगामी फिल्म द प्राइड ऑफ भारतः छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर चर्चा में हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित इस ऐतिहासिक ड्रामा में बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेरॉय पहले से अहम किरदारों में शामिल थे। ताजा अपडेट है कि एक और बालीवुड अभिनेत्री इस परियोजना का हिस्सा बन गई हैं,जो भूमि पेडनेकर हैं। ये पहला मौका होगा,जब फैंस उन्हें दक्षिण सिनेमा की फिल्म में डेब्यू करते हुए देखेंगे। मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर आधिकारि पोस्ट साझा करते हुए भूमि के परियोजना में शामिल होने की जानकारी दी है।उन्होंने बताया कि अभिनेत्री फिल्म में कर्नाटक की वीर योद्धा रानी बेलावड़ी मल्लम्मा का किरदार निभाएंगी, जिन्हें उनकी बहादुरी और अटूट साहस के लिए जाना जाता है।

खेल समाचार

कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत जीतने वाले राजा मुथुपंडी को सरकार का तोहफा

सीएम विजय ने 30 लाख के नकद इनाम का किया ऐलान...

चेन्नई,28जुलाई 2026। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 65 किग्रा में रजत पदक जीतने वाले वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी के लिए 30 लाख रुपये के नगद इनाम की घोषणा की है।

एथलीट को उनकी कामयाबी पर बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इनाम उनके शानदार प्रदर्शन के लिए है। सीएम ने भरोसा जताया कि उनकी कामयाबी राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।

विजय ने कहा, मैं ग्लासगो में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए राजा मुथुपंडी को दिल से बधाई देता हूं। उनकी सफलता तमिलनाडु के लिए बहुत गर्व की बात है। उनकी यह उपलब्धि हमारे युवाओं को प्रेरणा दे। मैं उन्हें और भी कई जीत की शुभकामनाएं देता हूं जो तमिलनाडु और देश दोनों के लिए सम्मान लाएंगी। मुख्यमंत्री विजय ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए युवा वेटलिफ्टर को दिल से बधाई दी। उन्होंने मुथुपंडी के परफॉर्मेंस को एक रिकॉर्ड बनाने वाली कामयाबी बताया और कहा कि उन्हें राज्य के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इंसेंटिव में से एक से सम्मानित किया जाएगा।

राजा को उनकी सफलता पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। राजा ने कुल 286 किग्रा (126 किग्रा+160 किग्रा) के साथ खत्म किया। राजा ने 125 किग्रा के सफल स्नैच से शुरुआत की और फिर अपनी दूसरी कोशिश में 126 किग्रा तक सुधार किया। वह अपनी आखिरी लिफ्ट में 129 किग्रा क्लियर नहीं कर पाए। क्लीन एंड जर्क में, उन्होंने 158 किग्रा और 160 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में 170 किग्रा पर फेल हो गए और दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक जीता।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान

नई दिल्ली,28जुलाई 2026। श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की हाई-वोल्टेज टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इस महत्वपूर्ण दौरे के लिए टीम की कमान युवा स्टार शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले भारतीय टीम अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए 7 अगस्त से कोलंबो के मैदान पर चार दिनों का एक अहम प्रैक्टिस मैच खेलेगी। हाल ही में जिम्बाब्वे को टी20 सीरीज में रौंदकर वापस आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 का ताज हासिल करने वाली टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं और वह श्रीलंका के घर में भी अपनी बादशाहत कायम रखने के इरादे से उतरेगी।

श्रीशंकर मुरली ने हासिल किया फाइनल का टिकट

ग्लासगो, 28 जुलाई 2026। भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार शुरुआत की है। उन्होंने पुरुषों की लॉन्ग जंप के क्वालिफिकेशन राउंड में 8.01 मीटर की छलांग लगाकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। श्रीशंकर ने ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन मार्क को आसानी से पार कर लिया।क्वालीफाइंग 'ग्रुप-ए' में 27 वर्षीय एथलीट को फाइनल में सीधा प्रवेश पाने के लिए कम से कम 8.00 मीटर की छलांग लगाने की जरूरत थी। श्रीशंकर ने यह लक्ष्य केवल एक प्रयास में हासिल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन राउंड समाप्त कर दिया और बुधवार को होने वाले मेडल इवेंट के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखी। केरल के इस एथलीट ने अपने पहले प्रयास से ही 'ग्रूप-ए' में शीर्ष स्थान हासिल किया। वे जमैका के जॉर्डन टर्नर से आगे रहे, जिनकी सर्वश्रेष्ठ छलांग 7.80 मीटर थी। अगर श्रीशंकर क्वालिफिकेशन मानक तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए दोनों क्वालिफिकेशन ग्रूप के 12 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शामिल होना पड़ता।इसके बजाय,भारतीय एथलीट ने शुरुआत से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और अपनी पहली छलांग से ही जरूरी मार्क को आसानी से पार करके किसी भी तरह की अनिश्चितता को दूर कर दिया।चोट से उबरकर इस सीजन में शानदार फॉर्म में वापसी करने वाले श्रीशंकर,भारत के लिए एथलेटिक्स में मेडल जीतने की सबसे मजबूत उम्मीदों में से एक के तौर पर ग्लासगो पहुंचे हैं। उनके नाम इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (8.38 मीटर) दर्ज है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में श्रीशंकर ने क्वालिफिकेशन राउंड में दबदबा बनाया था और सभी प्रतिस्पर्धियों में सर्वश्रेष्ठ छलांग (8.05 मीटर) लगाई थी, लेकिन फाइनल में मामूली अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गए थे। उन्होंने 8.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई थी,जो बहामास के लाक्वान नायरन के बराबर थी। नायरन ने अपनी दूसरी सर्वश्रेष्ठ छलांग बेहतर होने के कारण 'काउंटबैक नियम' के तहत गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब श्रीशंकर 29 जुलाई को फाइनल खेलेंगे, जिसमें उनके पास चार साल पहले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए सिल्वर मेडल का रंग बदलने को मौका है।

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मैं सरिता (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है), सुपुत्री गंगा राम, गॉव/शहर-करौंदी,पो. सलका, तहसील-उदयपुर,जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ ने अपना नाम - सरिता (SARITA) (पुराना नाम) से बदल कर सलिता (SALITA) (नया नाम) रख लिया है। आधार कार्ड में मेरा जन्मतिथि 01.01.2008 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया हैं, मेरा सही जन्मतिथि 07.10.2005 हैं,जो सत्य एवं सही है।

आवेदिका
सरिता
करौंदी,पो. सलका, तहसील-उदयपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

// सार्वजनिक उद्घोषणा/ ईश्तहार

क्रमांक/300/6/वाचक-2/2025
सूरजपुर दिनांक - 21/07/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम/नगर जमदेई प0ह0नं0... तहसील सूरजपुर जिला -सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक बिगन राम पिता/पति संक राम जाति बिझिया निवासी ग्राम जमदेई पोस्ट कन्दरई थना जयनगर तहसील सूरजपुर जिला -सूरजपुर (00) ने अपने पिता संत राम पिता लबदु का मृत्यु तिथि 10/06/2010 स्थान जमदेई के जन्म/मृत्यु पत्र हेतु आंवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति / आक्षेप हो तो वे स्वयं अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 04/08/2026 दिन..... को उपस्थित होकर दावा /आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 21/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील
नायब तहसीलदार
उप तह.मानी,सूरजपुर

न्यायालय लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजगनर जिला-सूरजपुर,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ग्राम पम्पापुर के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका विनोद साहू आ0/पति श्री प्रसाद साहू जाति तेली निवासी ग्राम पम्पापुर लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदक/आवेदिका अपने पिता स्व. श्री प्रसाद साहू का विलम्ब मृत्यू प्रमाण पत्र पंजीयन कराने बावत अनुलब्धता प्रमाण पत्र मय अन्य सहायक दस्तावेज के साथ न्यायलय में आवेदन पत्र पेश किया गया है। मृत्यु दिनांक 11/01/2011

अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वम । अथवा किसी विविध प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 31/7/2022 को न्यायालयीन समयवधि में उपस्थित कर दावा / आपत्ति पेश कर सकतें है । उसके पयचात दावा आपत्ति में कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 17/07/2026 को न्यायलीन पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया ।

सील
नायब तहसीलदार
लिंक कोर्ट देवनगर
जिला-सूरजपुर

मुख्यमंत्री साय छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में हुए शामिल

राज्य में खेलों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर,28 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के समापन सत्र में शामिल हुए। उन्होंने राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में विगत मार्च-अप्रैल में छत्तीसगढ़ में हुए देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न सत्रों में देशभर से आए खेल प्रशासकों,नीति निर्माताओं,स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स, नामचीन खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और खेल संघों के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं, खेल प्रतिभाओं की खोज,प्रशिक्षण और सुदृढ़ खेल अधोसंरचना के रोडमैप पर दिनभर मंथन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि विशेषज्ञों के बीच आज दिनभर हुए गंभीर विचार-विमर्श से राज्य में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के कार्यों को सार्थक एवं प्रभावी दिशा मिलेगी। राज्य में खेलों के विकास

के लिए यह कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने छत्तीसगढ़ में गंभीरता से काम हो रहे हैं। उत्कृष्ट खेल मिशन के अंतर्गत खेल अधोसंरचना को मजबूत करने इस साल के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने हाल ही में प्रदेशभर के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को मंजूरी दी है, जिन्हें आगे जाकर सरकार नौकरी में लाभ देगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खिलाड़ियों को खेलने के लिए अच्छा मंच उपलब्ध कराने बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन राज्य में हुए हैं। बस्तर ओलंपिक में करीब चार लाख और सरगुजा ओलंपिक में लगभग साढ़े तीन लाख खिलाड़ियों ने भागीदारी की है। राज्य की खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर और संसाधन देने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव कहा कि यह कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में बहुत मददगार होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों में प्राकृतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत युवा निकलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें तराशने और संवारने की कार्ययोजना पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विशेषज्ञों के जो अमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं, उन पर निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। आज के निष्कर्षों को शामिल कर हम विस्तृत कार्ययोजना बनाएंगे और उसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार,संचालक श्रीमती तनुजा सलाम,ओलंपियन जिन्सन जॉनसन,प्रख्यात शिक्षाविद एवं खेल वैज्ञानिक डॉ. रत्नेश सिंह, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया, हाई परफॉर्मेंस एनॉलिस्ट रोनक कोठारी,पीईएफआई के राष्ट्रीय सचिव डॉ. पियूष जैन,खेलो इंडिया के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान सहित प्रदेश के अनेक खिलाड़ी,प्रशिक्षक,सभी जिलों के खेल अधिकारी एवं खेल संघों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कॉन्क्लेव में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदकों सहित जीते थे कुल 19 पदक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के समापन सत्र में इस साल छत्तीसगढ़ में हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री साय ने इस वर्ष 3 अप्रैल को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के समापन समारोह में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदकों सहित कुल 19 पदक जीते थे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में निकिता ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं रिषिका कश्यप ने भारोत्तोलन, अनुष्का भगत ने तैराकी, लक्ष्मण सोढ़ी,अभिषेक,डमरू कुमार,गजेन्द्र ठाकुर और तिलक बारसे ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीते थे। मनीष कुमार ने एथलेटिक्स, निखिल खलको ने तैराकी और लक्की बाबू ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीते थे। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को दो लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को डेढ़ लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को एक लाख रुपए के चेक प्रदान किए। वहीं टीम खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला फुटबॉल टीम को 22 लाख रुपए,रजत पदक विजेता पुरूष फुटबॉल टीम को साढ़े 16 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाली पुरूष हॉकी टीम को 9 लाख रुपए की राशि दी गई।

रायगढ़ में 50 हजार रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार

रायगढ़,28 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ के राहत और आपदा प्रबंधन शाखा के बाबू को अरेस्ट किया गया है। वह सर्पदंश से हुई मृत्यु के एवज में मिलने वाली मुआवजा राशि को बैंक खाते में भुगतान कराने 50 हजार मांग रहा था। आरोपी को हस्ताक्षर वाले चेक के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक पुसौर तहसील के ग्राम बुलाकी के रहने वाले विजय सिदार ने एसीबी बिलासपुर में क्लर्क की शिकायत की थी। विजय सिदार ने बताया कि उसकी पत्नी रामकुमारी का देहांत सर्पदंश से साल 2023 में हो गया था। शासन की योजना के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि लेने के लिए उसके द्वारा राजस्व विभाग में आवेदन किया गया था। यह प्रकरण कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ में पेंडिंग था। इसके लिए उसने कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ के आपदा प्रबंधन शाखा के बाबू राजकुमार सिदार से मुलाकात की। विजय ने शिकायत में बताया कि बाबू राजकुमार सिदार ने मुआवजा राशि को उसके बैंक खाते में डालने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की जा रही है। मुआवजा राशि मिलने के बाद और 50 हजार लाकर देने कहा जा रहा है। एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच की। शिकायत सही मिलने पर मंगलवार को कार्रवाई की गई। टीम ने रायगढ़ कलेक्ट्रेट के राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के बाबू राजकुमार सिदार को प्रार्थी से 50 हजार रुपए का चेक लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसीबी के मुताबिक, रिश्वत की रकम की गारंटी के लिए हस्ताक्षर किया हुआ चेक मांगकर रिश्वत लेने और इस तरह पकड़े जाने का यह पहला मामला है।

खाद नहीं मिलने से किसानों का फूटा गुस्सा ढाई घंटे तक किया चक्काजाम,प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन

भानुप्रतापपुर,28 जुलाई 2026। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के ग्राम केंवटी लैम्प्स में रासायनिक खाद वितरण में अव्यवस्था को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। समय पर खाद नहीं मिलने और रात में चुनिंदा किसानों को खाद बांटने का आरोप लगाते हुए किसानों ने भानुप्रतापपुर-अंतागढ़ मुख्य मार्ग पर करीब ढाई घंटे तक चक्काजाम किया। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त किया। मंगलवार दोपहर बड़ी संख्या में किसान केंवटी लैम्प्स के सामने एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम शुरू कर दिया। किसानों का आरोप था कि वे पिछले पांच दिनों से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही। वहीं सोमवार देर रात कुछ प्रभावशाली लोगों के फोन आने पर चुनिंदा किसानों को खाद वितरित कर दिया गया,जिससे बाकी किसानों में भारी नाराजगी फैल गई। चक्काजाम की सूचना मिलते ही तहसीलदार कुलदीप ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर निष्पक्ष तरीके से खाद वितरण कराने और जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब ढाई घंटे से जारी चक्काजाम समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका। लैम्प्स के खाद प्रभारी राकेश चालाकी ने स्वीकार किया कि एक नेता के फोन आने के बाद मजबूरी में सोमवार रात एक किसान को खाद देना पड़ा।

बीजेपी नेता ने नक्सल मूवमेंट के नाम पर फैलाई दहशत,गिरफ्तार

कांकेर,28 जुलाई 2026। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिपली बुर्गी क्षेत्र में नक्सली बैनर-पोस्टर फर्जी निकले। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए भाजपा नेता शिवा अनिल मिस्त्री और सहयोगी रंजीत मलिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक, शिवा मिस्त्री कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 24 इरपानार से निर्वाचित सदस्य है। शिवा महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे क्षेत्र में खनन कंपनी के लिए पोकलेन मशीन और परिवहन का काम करता था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पिपली बुर्गी से 5 किसी दूर पर साइनबोर्ड के नीचे संदिग्ध लाल कपड़े का बैनर मिला, जिसमें नक्सली संगठन होने का दावा करते हुए धमकी दी गई थी।

कोन्टा पुलिस ने 223 किलो गांजा सहित 3 तस्कर पकड़े

फर्जी नंबर प्लेट वाली क्रेटा से राजस्थान ले जाई जा रही थी करोड़ों की खेप

पुलिस की बड़ी सफलता : 1 करोड़ से अधिक के गांजे की तस्करी नाकाम

सुकमा,28 जुलाई 2026। सुकमा जिले की कोन्टा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 223.020 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते राजस्थान के भीलवाड़ा जा रहे थे।

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही फर्जी नंबर प्लेट लगी क्रेटा कार, तीन मोबाइल फोन, नकद राशि और अन्य सामान जब्त किया है। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 1 करोड़ 27 लाख 26 हजार 600 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार,28 जुलाई की रात करीब 2 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की क्रेटा कार में भारी मात्रा में गांजा भरकर मलकानगिरी से कोन्टा होते हुए राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर

थाना कोन्टा पुलिस ने कृष्ण मंदिर चौक, ढोंढरा में नाकाबंदी की। जांच के दौरान संदिग्ध क्रेटा कार को रोककर तलाशी ली गई। कार से 110 पैकेटों में भरा 223.020 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 11 लाख 50 हजार रुपए है।

पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान दुर्गा शंकर खारोल (19),मनीष खारोल (21) और रामदेव खारोल (23) निवासी भीलवाड़ा,राजस्थान के रूप में बताई। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मलकानगिरी से गांजा खरीदकर राजस्थान में अधिक कीमत पर बेचने के लिए ले जा रहे थे।

जांच में खुला फर्जी नंबर प्लेट का खेल

वाहन की जांच के दौरान पुलिस को क्रेटा कार की नंबर प्लेट संदिग्ध लगी। इंजन और चेसिस नंबर का सत्यापन करने पर पता चला कि वाहन पर ओडिशा का फर्जी नंबर लगाया गया था, जबकि कार का वास्तविक पंजीयन राजस्थान का है। पुलिस का मानना है कि आरोपी पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे।

सप्लाई नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी),29 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अब पुलिस गांजे के स्रोत,सप्लाई नेटवर्क और इस तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

टीम की रही अहम भूमिका

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की और एसडीओपी प्रशांत देवांगन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवानंद तिवारी के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में थाना कोन्टा पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रायपुर में एक और नंगी पार्टी के आयोजन की तैयारी,सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहा पोस्टर

रायपुर,28 जुलाई 2026। राजधानी में रोजाना वीकेंड में नंगी पार्टियों का आयोजन किया जाता है इसी तर्ज पर एक बार फिर सोशल मीडिया में नंगी पार्टियों के पोस्टर जमकर वायरल होने लगे है। जिसके चलते इस मामले की जानकारी जनता से रिश्ता प्रेस ने रायपुर कमिश्नर को भी दे दी है। आपको बता दें कि जनता से रिश्ता पिछले कई सालों से राजधानी के होटलों फार्म हाऊसों में विभिन्न नामों से चल रहे विकेंड पार्टी का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित कर शासन प्रशासन और समाज को आगाह करते आ रहा है परंतु सफेद पोशों के कारण मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि यह संस्कृति को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास है एसे में समाज सुधारक भी नदारत हो गए है। वो सिर्फ अपने फायदे वाले काम में ही समाज सुधारकी बात करते है। रायपुर पुलिस ने नंगी पार्टी के सिंडिकेट संचालक और मुख्य आरोपी अजय महापात्र को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस बार फिर से नंगी पार्टियों का दौर चल पड़ा है। रायपुर में एक बार फिर आयोजित होने जाए रही नंगी पार्टी, सोशल मीडिया में हो रहा जमकर प्रचार राजधानी रायपुर

में बदलते लाइफस्टाइल के साथ पार्टी कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। बर्थडे पार्टी, फ्रेशर पार्टी, गेट टू गेदर, पूल पार्टी और थीम पार्टी जैसे आयोजनों का चलन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। लेकिन इसी के साथ कुछ आयोजनों में नियमों की अनदेखी, नशे की संभावित गतिविधियों और देर रात तक चलने वाली पार्टियों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। शहर में होने वाली कुछ कथित हाई प्रोफाइल पार्टियों को लेकर पुलिस और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी चर्चा तेज हो गई है। न्यूड पार्टी मामले में गिरफ्तार हुए थे ये आरोपी, मुख्य संचालक था आरोपी अजय महापात्रा हाल ही में रायपुर में एक पार्टी को लेकर पुलिस जांच सामने आई थी, जिसे सोशल मीडिया पर के नाम से प्रचारित किया गया था। पुलिस के अनुसार, आयोजकों ने 'अपरिचित क्लब' नाम से इंस्टाग्राम पेज बनाया था, जहां से पोस्टर, वीडियो और प्रचार सामग्री साझा की जाती थी। इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया पेजों से भी प्रमोशन किए जाने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद साइबर यूनिट के माध्यम से तकनीकी जांच शुरू की, जिसमें मोबाइल नंबर,पेमेंट ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी जानकारियां खंगाली गईं। यह मामला केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है,बल्कि शहर में तेजी से बढ़ते पार्टी कल्चर को लेकर व्यापक सवाल खड़े करता है।

एसी फटने से रायपुर मेकाहारा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग

रायपुर,28 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल (मेकाहारा) के मेडिसिन विभाग के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। दोपहर के समय हुए इस हादसे के तुरंत बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुँचकर कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि समय रहते अस्पताल स्टाफ, डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए वार्ड में भर्ती सभी मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटनाक्रम के अनुसार दोपहर में मेडिसिन विभाग के इमरजेंसी हिस्से में लगे एसी से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग फैल गई। देखते ही देखते पूरे वार्ड और आसपास के गलियारों में घना धुआं भर गया,

जिससे वहां मौजूद मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक एयर कंडीशनर (एसी) में शार्ट सर्किट होने या उसके कंप्रेसर में धमाका होने की वजह से यह हादसा हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुँचकर तुरंत मोर्चा संभाला और कुछ ही देर में स्थिति को नियंत्रित कर लिया। मेकाहारा प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ रोजाना हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। अस्पताल परिसर में एसी कंप्रेसर फटने की यह कोई पहली घटना नहीं है।

रवि भगत पुलिस हिरासत में स्कूल में अशांति फैलाने का आरोप

रायगढ़,28 जुलाई 2026। जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुपाकानी गांव में सरस्वती साइकिल वितरण योजना के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने साइकिलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सरकारी योजना में घटिया साइकिल वितरण किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी घेरा और योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में छात्राओं को सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलें दी जा रही थीं। इसी दौरान रवि भगत मौके पर पहुंचे और साइकिलों की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताई। आरोप है कि उन्होंने साइकिल लेने पहुंची छात्राओं से साइकिलें वापस करवाने को कहा, जिसके बाद मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रवि भगत ने आरोप लगाया कि छात्राओं को वितरित की जा रही साइकिलें गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। सरकारी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

रायपुर न्यायालय में फर्जी जमानत का खेल उजागर,3 महिलाएं गिरफ्तार

रायपुर,28 जुलाई 2026। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने न्यायालय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए फर्जी जमानतदार बनकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेने का प्रयास करने वाली तीन महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये महिलाएं फर्जी ऋण पुस्तिका और अन्य दस्तावेजों में हेरफेर कर न्यायालय में स्वयं को जमानतदार के रूप में प्रस्तुत कर रही थीं और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रही थीं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र कमिश्नरेट रायपुर तारकेश्वर पटेल ने थाना सिविल लाइन पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम ने न्यायालय परिसर में चल रही गतिविधियों पर नजर रखते हुए संदिग्ध

व्यक्तियों की जानकारी जुटानी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ महिलाएं फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से आरोपियों की जमानत लेने का काम कर रही हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने न्यायालय परिसर पहुंचकर मामले की जांच की। जांच के दौरान तीन महिलाएं संदिग्ध गतिविधियों में पाई गईं। पुलिस ने जब उनके दस्तावेजों की जांच की तो ऋण पुस्तिका में काट-छांट और छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई। पूछताछ में महिलाओं ने कथित रूप से फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर विभिन्न न्यायालयों में आरोपियों की जमानत लेने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर न्यायालय की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस मामले में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 401/2026 और अपराध क्रमांक 402/2026 दर्ज किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4),338, 336(3),340(2),238 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार की गई महिलाओं में पहली आरोपी सुनीता देवी राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम टेका हल्दी, थाना तिल्दा,जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) शामिल है। दूसरी आरोपी सरस्वती बाई सोनी उम्र 72 वर्ष निवासी उरला काली मंदिर के पास,डीडी कॉलोनी,थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)